

कांग्रेस ने ईसी पर भी उठाए सवाल
वोटिंग से पहले ‘कैश फॉर वोट’ का बवाल, केरल में सियासत गरमाई

एजेंसी ►► कोलकाता

केरल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी पारा चरम पर है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने एक कथित वीडियो जारी कर बड़ा आरोप लगाया है कि बीजेपी कार्यकर्ता वोट के बदले पैसे बांट रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक बुजुर्ग महिला को पैसे दिए जा रहे हैं और यह सब पार्टी उम्मीदवार की मौजूदगी में हो रहा है। साथ ही सतीशन ने कहा कि यह सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं है, बल्कि कई निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं को पैसे और साड़ियां बांटने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि 'यह केरल में पहली बार हो रहा है और बीजेपी वोटरों को प्रभावित करने के लिए नई व्यवस्था लागू कर रही है।' उनके मुताबिक, यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की गंभीर कोशिश है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

आयोग से हस्तक्षेप की मांग
कांग्रेस ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। सतीशन ने चेतावनी दी कि यदि संबंधित अधिकारी कार्रवाई नहीं करते, तो पार्टी कानूनी रास्ता अपनाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के ठीक पहले इस तरह की गतिविधियां चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन हैं। अलापप्पुझ में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी पलकड़ में पैसे बांटने के आरोपों को 'चीकने वाला' बताया।

कांग्रेस-एलडीएफ के आरोप झूठे : बीजेपी का पलटवार
भाजपा नेता एस सुरेश ने कांग्रेस और एलडीएफ के आरोपों को सिर से खारिज करते हुए पलकड़ में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि 'पलकड़ की जनता ने तय कर लिया है कि यहां से बीजेपी का विधायक बनेगा, इसी डर से कांग्रेस भ्रामक बयान दे रही है।' महिलाओं को पैसे बांटने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि ये 'गंभीर आरोप नहीं हैं' और संबंधित महिला खुद स्पष्ट कर चुकी हैं कि बीजेपी ने कोई पैसा नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और एलडीएफ हार के डर से झूठ फैला रहे हैं। सोमा सुरेंद्रन का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि जनता उन्हें ही विधायक चुने जे रही है। बीजेपी ने भरोसा जताया कि इस बार पलकड़ में जीत तय है।

लेफ्ट का भी आरोप- झंझर, पलकड़ के विधायक राहुल मामकूटथिल ने भी कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा, 'आप अपनी विचारधारा फैला सकते हैं, लेकिन पैसे के दम पर पलकड़ में एक भी वोट नहीं खरीदा जा सकता।' उन्होंने हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि एक उम्मीदवार के करीबी सहयोगी को जनता ने पैसे बांटते हुए पकड़ा था, जो बेहद आपत्तिजनक है।

व्हाइट हाउस के बाहर हो रहा हंगामा
बड़ी संख्या जुटे प्रदर्शनकारी

सीजफायर के बाद ट्रंप से 85 सांसदों ने मांगा इस्तीफा



एजेंसी ►► वाशिंगटन

एक महीना बाद मिडिल ईस्ट में 2 हफ्तों के लिए सीजफायर हो गया है। इसे ईरान और अमेरिका समेत कई देशों के लिए अच्छा बताया जा रहा है। एक तरफ ईरान के साथ सीजफायर की बात से अमेरिका में राहत देखी जा रही है। दूसरी तरफ सीजफायर के बाद अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। सीजफायर का ऐलान होते ही बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी व्हाइट हाउस पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप के इस्तीफे की मांग की है। लोगों के अलावा 85 सांसदों ने भी ट्रंप के इस्तीफे की मांग की है। कई सांसद और नेता कह रहे हैं कि ट्रंप का ईरान युद्ध को लेकर बार-बार शब्द बदलना, रणनीति बदलना और यह गाली भरा पोस्ट लिखना, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाता है।

सरकारी कर्मचारियों के आतंकियों से संबंध
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से संबंधों के आरोप में दो सरकारी कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी है। सूत्रों के मुताबिक लंबे समय से इन कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। बर्खास्त

रातमर से जमे हैं प्रदर्शनकारी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्धविराम की घोषणा के बाद प्रदर्शनकारी व्हाइट हाउस के बाहर जमा हुए हैं। प्रदर्शनकारी मॉर्गन टेलर ने कहा कि हम आज रात यहां इसलिए आए हैं क्योंकि हम मौजूदा हालात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम चुनाव तक इंतजार नहीं कर सकते। इस देश में जो हो रहा है उसे अभी रोकना होगा। न केवल इस देश में बल्कि दुनिया भर में हो रही क्रूरता, इस राष्ट्रपति द्वारा व्हाइट हाउस से किए गए युद्ध अपराध – इस आदमी को जाना ही होगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केवल एक आदमी को ही नहीं बल्कि पूरे शासन को जाना होगा।

किए गए लोगों में से एक, रामबन जिले के शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी फरहत अली खंडे पर आरोप है कि वह हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम कर रहा था। दूसरा कर्मचारी, बांदीपोरा का मोहम्मद शफी डार, ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत था।

टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने लगाए गंभीर आरोप

चुनाव आयोग ने तृणमूल नेताओं को सात मिनट में भगाया, बढ़ा विवाद

एजेंसी ►► कोलकाता

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और निर्वाचन आयोग (ईसी) के बीच कड़वाहट अपने चरम पर पहुंच गई है। बुधवार को दिल्ली में चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ और टीएमसी प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई महज सात मिनट की मुलाकात एक बड़े विवाद के साथ समाप्त हुई। टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि, चुनाव आयोग की तरफ से भी बफाई दी गई और टीएमसी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। डेरेक ओ'ब्रायन ने दावा किया कि जब प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के अधिकारियों के तबादलों और भाजपा के साथ उनके कथित संबंधों के सबूत सौंपे तो मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने उनसे कहा कि 'दफा हो जाओ'। टीएमसी का कहना है कि 10:02 एएम पर शुरू हुई यह बैठक 10:07 एएम पर ही खत्म हो गई। ओ'ब्रायन के अनुसार, ज्ञानेश कुमार के अलावा किसी अन्य चुनाव आयुक्त ने एक शब्द भी नहीं बोला।

ममता ने भवानीपुर से भरा नामांकन, दिखाई ताकत

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को भवानीपुर सीट से बतौर तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने से पहले सीएम ममता ने पैदल मार्च दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में टीएमसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि मैं आप लोगों से अपील करती हूँ न सिर्फ भवानीपुर में बल्कि बंगाल की सभी 294 सीटों पर वे टीएमसी की जीत सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा 'मुझे सचमुच बहुत दुख है कि एसआईआर के दौरान बंगाल की वोटर लिस्ट से इतने सारे नाम हटा दिए गए हैं।

800 मीटर पैदल चलकर नामांकन करने पहुंची ममता

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए अपने आवास से रवाना हुईं तो उनके साथ समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद थी। आपने फिर अंजना में हाथ जोड़कर ममता बनर्जी ने खडक के दोनों ओर कतार में खड़े पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का अभिवादन किया। वह लगभग 800 मीटर पैदल चलकर अलीपुर सर्वे बिल्डिंग पहुंचीं जहां नामांकन पत्र दाखिल किया।

आयोग बोला चिल्लाने लगे थे डेरेक बंगाल चुनाव के बीच महसांग्राम



टीएमसी नेताओं ने चिल्लाकर बात की : आयोग

दूसरी ओर, चुनाव आयोग के सूत्रों ने टीएमसी के दावों को सिर से खारिज करते हुए इसे झूठ करार दिया है। पीटीआई ने आयोग के सूत्रों के हवाले से कहा है कि डेरेक ओ'ब्रायन चुनाव आयुक्तों पर चिल्ला रहे थे और उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को बोलने तक नहीं दिया। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कथित तौर पर ओ'ब्रायन से मर्यादा बनाए रखने का अनुरोध किया और कहा कि 'चीख-चिल्लाना और उमड़-धुमड़ आयोग के कक्ष में उचित नहीं है। सूत्रों ने बताया कि सीईसी ने टीएमसी नेताओं से केवल सीधी और स्पष्ट बात की थी, जिसे वे पचा नहीं पाए।

एसआईआर पर छिड़ी है रार
चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद आयोग ने बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी और गृह सचिव सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर दिया था, जिसे ममता बनर्जी ने एकतरफा और अमृतपूर्व बताया। वहीं, टीएमसी का आरोप है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के नाम पर बंगाल के लाखों वैध मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। विपक्षी दलों ने चुनाव को एक या दो चरणों में कराने की मांग की थी, लेकिन आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए इसे दो चरणों (23 अप्रैल और 29 अप्रैल) में कराने का निर्णय लिया है।

बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में होना है मतदान

‘चुनाव आयोग ने टीएमसी का नाम लेकर दी चेतावनी

भारत निर्वाचन आयोग (ईसी) ने पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों को लेकर एक बेहद सख्त और स्पष्ट संदेश जारी किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपने आधिकारिक हैंडल से एक पोस्ट करते हुए, चुनाव आयोग ने राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को सीधे तौर पर 'दो टुक' शब्दों में चेतावनी दी है कि इस बार के चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी और शांतिपूर्ण होंगे। आयोग ने अपनी पोस्ट में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए स्पष्ट किया है कि चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या बाहुबल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

आयोग की पोस्ट
अपनी पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने लिखा, 'चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को दो टुक। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव: भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छाप रहित, बुध एवं सोर्स जाँगीम रहित होकर हो रहेगें।'

कांग्रेस को सात सीटों पर उम्मीदवार बदलने पड़ गए

बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही हैं। कांग्रेस ने भी दूसरे चरण के चुनाव के लिए बुधवार को अपनी एक सूची जारी की, लेकिन उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिला। पार्टी ने पहले से घोषित उम्मीदवारों में से 7 सीटों पर बदलाव किया है। कांग्रेस ने कई सीटों पर उम्मीदवार बदलते हुए नई सूची जारी की है। नाकाशिपारा से गोलाम किबेरिया मंडल की जगह ताहिर एसके को उतार दिया गया है। छपरा में रहीदुल मंडल के स्थान पर आसिफ खान चुनाव लड़ेंगे, हावड़ा से एणब भट्टाचार्य को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं, बीजेपी ने भी पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए अपनी छठी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने कोलकाता पोर्ट सीट से राकेश सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है।

युद्धविराम के बाद सोना और चांदी के दाम में जबर्दस्त तेजी

नई दिल्ली। अमेरिका और ईरान के दो हफ्ते के युद्धविराम पर सहमत होने के बाद मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतें 11,000 रुपये बढ़कर 2.51 लाख रुपये प्रति किलोग्राम हो गईं, जबकि सोना बढ़कर 1.56 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। अखिल भारतीय सराफा संघ ने कहा कि चांदी की कीमत मंगलवार के बंद स्तर 2,40,000 रुपये प्रति किलोग्राम से 11,000 रुपये यानी लगभग पांच प्रतिशत बढ़कर 2,51,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी कर मिलाकर) हो गई। वहीं, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना भी 3,200 रुपये यानी 2.09 प्रतिशत बढ़कर 1,56,400 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी कर समेत) हो गया। पिछले बाजार सत्र में यह 1,53,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। विश्लेषकों ने कहा कि पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव कम होने से सर्राफा कीमतें मजबूत हुईं, जिससे वैश्विक वित्तीय बाजार में बड़ी राहत वाली तेजी शुरू हुई। एचडीएफसी सिक्कोरिटीज में शोध विश्लेषक (जिंस) सोमिल गांधी ने कहा कि सोने में मजबूत बढ़त बनी रही और बुधवार को यह तीन हफ्ते के उच्च स्तर पर पहुंच गया, क्योंकि वैश्विक जोखिम लेने की धारणा में सुधार के साथ डॉलर और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से कीमती धातुओं की मांग बढ़ी।

उदलगुड़ी, असम में कांग्रेस को झटका

मतदान से एक दिन पहले उम्मीदवार ने छोड़ी पार्टी

एजेंसी ►► गुवाहटी



यह कहा दैमरी ने

इससे पहले दोपहर में दैमरी ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। कांग्रेस में रहने का कोई फायदा नहीं है। इसने मेरे साथ धोखा किया है। उन्होंने आरोप लगाया, कांग्रेस केवल मिया समुदय के लिए काम करती है। लेकिन मेरे जैसे अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए कुछ नहीं करती।

मीडिया के सामने इस्तीफे की घोषणा की है। लेकिन उन्होंने पार्टी को अभी तक इस्तीफा नहीं सौंपा है।

स्टालिन सरकार के 5 वर्ष में त्रस्त हो गई जनता : पलानी



एजेंसी ►► चेन्नई

तमिलनाडु की राजनीति में चुनावी सरगमी तेज हो गई है। एआईएडीएमके प्रमुख एडप्पादी के पलानीस्वामी ने वेंलाचेरी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सत्तारूढ़ डीएमके सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने जनता से इसे सत्ता से हटाने की अपील की है। उन्होंने मुख्यमंत्री स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार को फेल मॉडल करार देते हुए आरोप लगाया कि यह सरकार अपने वादे पूरे करने में पूरी तरह नाकाम रही है। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पलानीस्वामी ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में डीएमके शासन

पिछले 11 वर्षों में स्वरोजगार व छोटे उद्योगों को गति दी मुद्रा योजना ने छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप को मजबूत बनाया

एजेंसी ►► नई दिल्ली

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 11 वर्षों में छोटे कारोबारियों और स्टार्टअप को बिना गारंटी ऋण देकर उन्हें मजबूत बनाया है और स्वरोजगार तथा छोटे उद्योगों को नई गति दी है। सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर अमित शाह ने कहा कि मुद्रा योजना के 11 वर्षों में 58 करोड़ ऋण वितरित किए गए हैं, जिनकी कुल राशि 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। इससे 12 करोड़ युवाओं को लाभ मिला है और आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा को नई गति मिली है। शाह ने कहा, 'मुद्रा योजना के 11 वर्षों में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बिना गारंटी ऋण देकर छोटे कारोबारियों और नए उद्यमों को सशक्त बनाया है, जिससे

20 लाख तक ऋण दिया जा रहा

यह योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आठ अप्रैल 2015 को शुरू की थी। इसके जरिए बिना किसी गारंटी के 20 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है।

मुद्रा योजना के 11 वर्षों में 58 करोड़ ऋण वितरित किए गए



स्वरोजगार और छोटे उद्योगों को नई ताकत मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि हर तीन में दो मुद्रा ऋण महिलाओं को दिए जाना महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

पेंट और टायर कंपनियों के शेयरों की चमक भी बढ़ी

पेंट कंपनियों के शेयरों पर भी क्रूड में गिरावट का असर दिखा। पेंट कंपनियां उत्पादन में क्रूड ऑयल का इस्तेमाल करती हैं। एशियन पेंट का शेयर उछाल के साथ 2288 रुपये पर बंद हुआ। कंसई नेरोलक पेंट का शेयर 5.19 फीसदी उछाल के साथ 187.61 रुपए पर चल रहा था। 8 अप्रैल को टायर कंपनियों के शेयरों में भी तेजी देखने को मिली। टायर कंपनियां उत्पादन में क्रूड ऑयल का इस्तेमाल करती हैं। सीएट का शेयर 4.33 फीसदी के उछाल 3,540 रुपए पर बंद हुआ। अपोलो का शेयर 5.85 फीसदी की तेजी के साथ 437 रुपए पर ट्रेड किया था। एमआरएफ का शेयर 5.63 फीसदी की तेजी के साथ 1,32,810 रुपए बंद हुआ।

गिरावट का सबसे ज्यादा फायदा डाउनस्ट्रीम कंपनियों को हुआ

क्रूड की कीमतें 15% तक क्रैश, ऑयल कंपनियों के शेयर उछले

एजेंसी ►► नई दिल्ली

वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में आई तेज गिरावट ने भारतीय ऑयल कंपनियों के शेयरों में बड़ा उतार-चढ़ाव पैदा कर दिया है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ दो हफ्ते के सीजफायर की घोषणा के बाद कच्चे तेल की कीमतों में करीब 15—17 प्रतिशत की भारी गिरावट देखी गई। इसका सीधा असर भारतीय शेयर बाजार में ऑयल सेक्टर पर पड़ा। तेल की कीमतों में गिरावट का सबसे ज्यादा फायदा डाउनस्ट्रीम कंपनियों को हुआ, जैसे एचपीसीएल, आईओसी और बीपीसीएल। इन कंपनियों का काम कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल-डीजल बनाना होता है। कच्चा तेल सस्ता होता है, तो इनकी लागत घटती है, मुनाफा बढ़ता है। यही वजह है कि इनके शेयरों में 6 से 10 प्रतिशत तक की तेजी देखी गई।

एचपीसीएल में जबर्दस्त तेजी

एचपीसीएल में जबर्दस्त तेजी देखी गई। कंपनी के शेयर 8 अप्रैल 2026 को 10.09 प्रतिशत उछलकर 364.95 रुपए पर बंद हुआ। दूसरी ओर अपस्ट्रीम कंपनियों के लिए यह गिरावट नुकसानदायक साबित हुई। ऑयल और नेचुरल गैस कंपरेशन और ऑयल इंडिया जैसी कंपनियों के शेयर 8 अप्रैल 2026 को 3.43 प्रतिशत तक गिर गए। ये कंपनियां सीधे कच्चे तेल का उत्पादन करती हैं, इसलिए तेल की कीमत गिरने से उनकी कमाई पर असर पड़ता है। कच्चे तेल में हर 1 डॉलर की गिरावट से ओएनजीसी के राजस्व पर 300-400 करोड़ रुपए का असर पड़ सकता है।

इंटरग्लोबल एविएशन का शेयर 9 फीसदी उछला

इंटरग्लोबल एविएशन के शेयरों को 8 अप्रैल को पूंज लग गए। दोपहर में यह शेयर 9.02 फीसदी उछाल के साथ 4,654 रुपए पर चल रहा था। सस्ते क्रूड से कंपनी की ऑपरेशनल कॉस्ट में कमी आएगी, जिससे उसका मार्जिन बढ़ेगा। 28 फरवरी को मध्यपूर्व में लड़ाई शुरू होने के बाद से इस शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। अगर क्रूड में और नरमी आती है तो यह एविएशन कंपनियों के लिए अच्छा होगा। 8 अप्रैल को स्पेइजेट के शेयरों में भी तेजी दिखाई। 5 फीसदी चढ़ने के बाद इस शेयर में अपर सर्किट लग गया।



चिंतन

मध्यपूर्व में युद्धविराम दुनिया को देगा राहत

मध्यपूर्व की बारूदी जमीन पर 40 दिन तक चले संघर्ष के बाद अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच घोषित दो सप्ताह का युद्धविराम निस्संदेह दुनिया के लिए राहत की सांस लेकर आया है। यह विराम केवल गोलियों और मिसाइलों की खामोशी भर नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार और आम आदमी की रसोई तक फैले संकट से अस्थायी निजात का संकेत भी है। सवाल यह है कि क्या यह युद्धविराम स्थायी शांति की प्रस्तावना है या सिर्फ एक खतरनाक संघर्ष का छोटा सा ‘पॉज’? हालाँकि उम्मीद की जा सकती है कि अब दुनिया को कुछ राहत मिलेगी। इससे तेल, गैस, उर्वरकों और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। ईरान और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जिद्द ने पूरी दुनिया को संकट में धकेल दिया था। होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने से इस लड़ाई की आंच लोगों की रसोई तक पहुंच गई थी। श्रमिकों, व्यापारियों और आमजन समेत हर वर्ग पर इसका व्यापक असर साफ देखा गया था। तेल, रसोई गैस और उर्वरक तक महंगे हो गए थे। होर्मुज खुलने से तेल, गैस और खाद्य पदार्थ आसानी से लोगों तक पहुंच सकेंगे। उम्मीद की जा सकती है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान दोबारा ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। होर्मुज जलडमरूमध्य पर मंडराते खतरे ने वैश्विक जरूरतें खाड़ी क्षेत्र पर निर्भर हैं। यदि आपूर्ति बहाल रहती है, तो आगामी वर्षा ऋतु में किसानों की कमर तोड़ दी। भारत जैसे कृषि-प्रधान देश में इसका सीधा असर खेत और रसोई दोनों पर दिखा। महंगे उर्वरकों ने किसानों की लागत बढ़ाई तो रसोई गैस और खाद्य पदार्थों की कीमतों ने आम आदमी की थाली को प्रभावित किया। ऐसे में यह युद्धविराम आर्थिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। इससे तेल और गैस की आपूर्ति सामान्य होने की उम्मीद जगी है, जिससे महंगाई पर कुछ अंकुश लग सकता है। भारत, चीन और ब्राजील जैसे बड़े कृषि उत्पादक देशों के लिए यह राहत इसलिए भी अहम है, क्योंकि उनकी उर्वरक जरूरतें खाड़ी क्षेत्र पर निर्भर हैं। यदि आपूर्ति बहाल रहती है, तो आगामी कृषि सत्र अपेक्षाकृत स्थिर रह सकता है, लेकिन इस राहत के पीछे छिपी कड़वी सच्चाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह युद्धविराम किसी स्थायी समाधान का परिणाम नहीं, बल्कि परिस्थितियों की मजबूरी का उत्पाद है। अमेरिका में चुनावी दबाव, इजराइल की सैन्य रणनीति और ईरान की क्षेत्रीय पकड़ इन सबके बीच यह समझौता हुआ है। यह शांति की इच्छा से ज्यादा, थकान और दबाव का समझौता प्रतीत होता है।सबसे बड़ी चिंता यह है कि यह युद्धविराम केवल दो सप्ताह के लिए है। इतने कम समय में दशकों पुराने अविश्वास, वैचारिक टकराव और सामरिक प्रतिस्पर्धा को खत्म करना लगभग असंभव है। पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहलू है क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की भूमिका। पाकिस्तान के जरिए हुई मध्यस्थता ने भले ही अस्थायी राहत दिलाई हो, लेकिन यह भी साफ है कि बिना व्यापक और ईमानदार कूटनीतिक प्रयासों के स्थायी समाधान संभव नहीं है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक शक्तियों को इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। कहा जा सकता है कि अगर इस अवसर को गंभीर कूटनीतिक पहल, आपसी विश्वास निर्माण और दीर्घकालिक रणनीति से नहीं जोड़ा गया, तो यह केवल एक विराम बनकर रह जाएगा, जिसके बाद संघर्ष और अधिक तीव्रता के साथ लौट सकता है। दुनिया को अब युद्धविराम से आगे बढ़कर शांति की स्थायी इबारत लिखनी होगी। इसके लिए सभी शक्तिशाली देश प्रयास करें।

आर्थिकी

अनिरुद्ध प्रताप सिंह



बाजार की चाल, अस्थिर रुपया और आरबीआई की सीमाएं

पिछले कुछ समय से वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव, विशेषकर ईरान-अमेरिका-इजराइल के बीच जारी संघर्ष ने भारत की अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित किया है और इसका सबसे स्पष्ट असर रुपये पर देखने को मिला है। पिछले दो हफ्तों में रुपये का व्यवहार लगभग वैसा ही रहा है जैसा आर्थिक सिद्धांत बताते हैं, यानी जैसे-जैसे जोखिम बढ़ा, पूंजी बाहर निकली, तेल महंगा हुआ और घरेलू मुद्रा दबाव में आ गई। रुपये में आई तेज गिरावट केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह उस गहरे असंतुलन का संकेत है, जो वैश्विक और घरेलू कारकों के मिलन से पैदा हुआ है। यह स्थिति इस बात को भी उजागर करती है कि जब बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी तेजी से बाहर निकलती है, तो भारत का भुगतान संतुलन उतना मजबूत सुरक्षा कवच नहीं रह जाता, जितना सामान्य परिस्थितियों में माना जाता है। इस घटनाक्रम की शुरुआत ऊर्जा बाजार से हुई। युद्ध के कारण तेल की आपूर्ति पर खतरा बढ़ा और कीमतों में तेजी आई। भारत जैसे देश, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है, उन्हें अधिक डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया कमजोर होता है। इसी के साथ विदेशी निवेशकों का भरोसा भी डगमगाया और उन्होंने भारतीय बाजारों से पैसा निकालना शुरू कर दिया। परिणामस्वरूप डॉलर की उपलब्धता और कम हो गई, जिससे रुपये पर दोहरा दबाव पड़ा। यह वही स्थिति है, जिसे अर्थशास्त्र में मांग और आपूर्ति के सरल सिद्धांत से समझाया जाता है-जब डॉलर की मांग बढ़ती है और आपूर्ति घटती है, तो उसकी कीमत बढ़ती है और रुपया गिरता है। 30 मार्च आते-आते यह स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि रुपया अपने इतिहास के सबसे कमजोर स्तर के करीब पहुंच गया, दिन के दौरान लगभग 95 प्रति डॉलर तक फिसल गया। पूरे वित्तीय वर्ष में रुपये में लगभग 11 प्रतिशत की गिरावट यह दिखाती है कि यह केवल अल्पकालिक उतार-चढ़ाव नहीं, बल्कि एक संरचनात्मक दबाव है। असली कहानी केवल स्फॉट रेट की नहीं है, बल्कि उस व्यापक वित्तीय अस्थिरता की है जो इसके पीछे काम कर रही थी। ऐसा कि हम जानते हैं कि जब भूराजनीतिक तनाव बढ़ता है, तो उसका असर केवल शेरार बाजार या मुद्रा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी वित्तीय प्रणाली में फैल जाता है। विदेशी मुद्रा बाजार में यह अस्थिरता सबसे पहले दिखाई देती है, जहां रुपये और डॉलर की कीमतें तेजी से बदलने लगती हैं। बैंक और डीलर इस जोखिम को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे इसे स्प्रेड यानी खरीद और बिक्री के दाम के अंतर के रूप में ग्राहकों पर डाल देते हैं। सामान्य समय में यह अंतर बहुत कम होता है, लेकिन जब बाजार में घबराहट बढ़ती है, तो यही स्प्रेड बढ़ जाता है और हर लेन-देन महंगा हो जाता है। इस बार स्थिति और जटिल इसलिए हो गई है, क्योंकि बाजार में असंतुलन बहुत बढ़ गया है। सामान्यतः भारत के अंदर और विदेशों में रुपये की कीमत लगभग समान रहती है, लेकिन जब इन दोनों के बीच अंतर बढ़ने लगे, तो यह बाजार में गड़बड़ी और अनिश्चितता का संकेत होता है। इसी अंतर का फायदा उठाने के लिए ट्रेडर्स सक्रिय हो गए और आर्विट्राज के जरिए लाभ कमाने लगे। 30 मार्च को डॉलर-रुपया बाजार में कुल लेन-देन लगभग 302 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो असामान्य रूप से अधिक था। इस पूरे तंत्र के केंद्र में एक असहज सच्चाई भी है-विदेशी मुद्रा बाजार केवल अस्थिरता को झेलता ही नहीं, बल्कि उससे लाभ भी कमाता है। बैंक और वित्तीय संस्थाएं बढ़ते स्प्रेड के जरिए ज्यादा मुनाफा कमाती हैं। इसके अलावा, उनके ट्रेजरी डेस्क की रुपयें की कीमत लगातार बढ़ती हैं, जिसे तकनीकी रूप से जोखिम प्रबंधन कहा जाता है, लेकिन वास्तविकता में यह भी एक प्रकार की सट्टेबाजी होती है। ऑनशोर बाजार और ऑफशोर नॉन-डिलीवरेबल फॉरवर्ड (एनडीएफ) के बीच का अंतर इस खेल को और बढ़ाता है। युद्ध, पूंजी का तेज बहिर्वाह, डॉलर की मजबूती और वैश्विक बाजारों की अस्थिरता जैसी स्थितियों से मुकाबले के लिए आरबीआई के पास सीमित उपकरण हैं, जैसे व्याज दरों में बदलाव या विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग। जब बाहरी दबाव बहुत अधिक होता है, तो ये उपाय पूरी तरह प्रभावी नहीं हो पाते। यही कारण है कि आज का संकट केवल नीति की विफलता नहीं, बल्कि एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था का परिणाम है, जिसमें राष्ट्रीय संस्थाओं की सीमाएं स्पष्ट हो जाती हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए केवल अल्पकालिक हस्तक्षेप पर्याप्त नहीं, बल्कि एक मजबूत, पारदर्शी और गहरे घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार का निर्माण करना होगा, ताकि बाहरी झटकों का असर प्रभावी ढंग से कम किया जा सके।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)



महिला आरक्षण बिल

नरेंद्र मोदी

16 अप्रैल को संसद की ऐतिहासिक बैठक होगी। महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के बाद उसे पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। इसे सिर्फ एक विधायी प्रक्रिया कहना इसके महत्व को कम करके आंकना होगा। यह भारतवर्ष की करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। हमारी नारी शक्ति देश की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आज देश के हर सेक्टर में नारी शक्ति मिसाल बन रही है। हमारे पारंपरिक मूल्य बताते हैं कि कोई भी समाज तभी प्रगति करता है, जब माताओं-बहनों को आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा मौके मिलते हैं।

नारी शक्ति का सशक्तिकरण जरूरी

इक्कीसवीं सदी की विकास यात्रा में हमारा भारत एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण की ओर आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में हम अपने लोकतंत्र को और मजबूत करने वाली एक बड़ी पहल के साक्षी बनने वाले हैं। यह ऐसा अवसर है, जब समानता, समावेशन और जनभागीदारी के प्रति हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता एक नए रूप में सामने आएगी। यह ऐसा समय है, जब हमारे देश की ऐसी कदम आगे महत्वपूर्ण दायित्व निभाना है। उसे ऐसा कदम आगे बढ़ाना है, जो हमारे लोकतंत्र को अधिक व्यापक एवं और अधिक प्रतिनिधिक बनाए। संसद का यह निर्णय महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नई शक्ति देना और लोकसभा और विधानसभाओं संस्थाओं में उनका उचित स्थान सुनिश्चित करेगा। आने वाले दिनों में भारत के अलग-अलग हिस्सों में अनेक पर्व मनाए जाएंगे। असम के लोग रंगाली बिहू मनाने वाले हैं और ओडिशा में महा विशुबा पणा संक्रांति का उत्सव मनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में पोइला बैशाख के साथ बंगाली नववर्ष की शुरुआत होगी। केरलम में विषु पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। तमिलनाडु के लोग उत्सुकता से पुयांडु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो पंजाब और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में लोगों को बैसाखी के पर्व का इंतजार है। हमारे ये पावन पर्व हर किसी में एक नई आशा का संचार करने वाले हैं। भारत के साथ-साथ दुनियाभर में इन त्योहारों को मनाने वाले सभी लोगों में हमदय से शुभकामनाएं देता हूं। मैं ये कामना करता हूं कि ये दिव्य और पावन अवसर हम सभी के जीवन में सुख-समृद्धि लेकर आएँ। इसी दौरान 11 अप्रैल से महात्मा फुले की 200वीं जयंती के समारोह भी शुरू होंगे। 14 अप्रैल को हम भारतवासी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की जयंती मनाएंगे। ये दोनों तिथियां हमें सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा के उन मूल्यों की भी याद दिलाती हैं, जिन्होंने आधुनिक होते भारत की दिशा तय की हैं। इन्हीं प्रेरणादायी अवसरों के बीच, 16 अप्रैल को संसद की ऐतिहासिक बैठक होगी। महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के बाद उसे पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। इसे सिर्फ एक विधायी प्रक्रिया कहना इसके महत्व को कम करके आंकना होगा। यह भारतवर्ष की करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। हमारी नारी शक्ति देश की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आज देश के हर सेक्टर में नारी शक्ति मिसाल बन रही है। साईंस एंड टेक्नोलॉजी से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक, खेल के मैदान से लेकर सशस्त्र बलों तक और संगीत से लेकर

कला के क्षेत्र में महिलाएं अपनी सशक्त पहचान बना रही हैं। हमारी माताएं-बहनें और बेटियां देश की प्रगति में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। हमारे पारंपरिक मूल्य बताते हैं कि कोई भी समाज तभी प्रगति करता है, जब माताओं-बहनों को आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा मौके मिलते हैं। इसी सोच के साथ बीते 11 वर्षों में महिला सशक्तिकरण के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार करने पर जोर दिया गया है, इसके लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। शिक्षा तक बढ़ती पहुंच, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, वित्तीय समावेशन में बढ़ोतरी और बुनियादी सुविधाओं तक बेहतर पहुंच ने आर्थिक और सामाजिक जीवन में महिलाओं की



भागीदारी को मजबूती दी है। ये भी सच्चाई है कि इन सारे प्रयासों के बावजूद राजनीति और विधायी संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व समाज में उनकी भूमिका के अनुरूप नहीं रहा है। इस कमी को अब दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि जब महिलाएं प्रशासन चलाने और प्रशासनिक निर्णयों में हिस्सा लेती हैं, तो उनका अनुभव और विजन बहुत काम आता है। इससे चर्चा तो समृद्ध होती ही है, क्वालिटी ऑफ गवर्नंस में सुधार भी होता है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना केवल प्रतिनिधित्व का विषय नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र को अधिक संवेदनशील, अधिक संतुलित और अधिक उत्तरदायी बनाने का प्रयास है। पिछले कई दशकों में लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं को उनका उचित स्थान दिलाने के लिए बार-बार प्रयास हुए हैं। समितियां गठित की गईं, विधेयकों के मसौदे प्रस्तुत किए गए, लेकिन वे कभी पारित नहीं हो सके। फिर भी, इस बात पर व्यापक सहमति रही है कि विधायी निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। सितंबर 2023 में संसद ने सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। यह मेरे जीवन के सबसे विशेष अवसरों में से एक रहा है। अब जरूरत

है कि 2029 के लोकसभा चुनाव और आने वाले समय में राज्यों के विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण के प्रावधानों के साथ कराए जाएं। महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने का यह अवसर हमारे संविधान की मूल भावना के साथ गहराई से जुड़ा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी, जहां समानता न केवल संविधान में निहित हो, बल्कि उसे व्यवहार में भी लाया जाए। विधायी संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना, उस परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है। यह एक ऐसे समाज के निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसमें राष्ट्र का भविष्य तय करने में प्रत्येक नागरिक की समान भूमिका हो। अब इस निर्णय को और टाला नहीं जा सकता। दशकों से इसकी आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। इस पर चर्चा हुई है, इसे बार बार दोहराया गया है। अगर अब भी हम इसे आगे टालते हैं, तो उसका अर्थ यही होगा कि हम उस असंतुलन को और लंबा खींच रहे हैं, जिसे हम पहचानते भी हैं और सुधारने की क्षमता भी रखते हैं। आज भारत पूरे आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए ये जरूरी है कि हमारी संस्थाएं सभी नागरिकों, विशेष रूप से हमारी आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं की आकांक्षाओं का सम्मान करें। इससे न सिर्फ दशकों पुराना संकल्प पूरा होगा, बल्कि विकास की गति को बनाए रखने में भी बहुत मदद मिलेगी। यह हमारे लोकतंत्र को अधिक उत्तरदायी बनाने और भविष्य के अनुरूप तैयार करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। यह किसी एक सरकार, एक दल या एक व्यक्ति का विषय नहीं है। यह पूरे राष्ट्र का विषय है। हमें मिलकर इस कदम के महत्व को समझना है और मिलकर ही इसे साकार करना है। यही हमारी नारी शक्ति के प्रति हमारा दायित्व भी है, इसलिए महिला आरक्षण बिल को पारित कराने के लिए सहमति बहुत जरूरी है। इसे बड़े राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर देखा जाना चाहिए। ऐसे अवसर हमें यह याद दिलाते हैं कि कुछ फैसले अपने समय से बड़े होते हैं। वे आने वाली पीढ़ियों की दिशा तय करते हैं। संसद का यह ऐतिहासिक सत्र करीब आ चुका है। मैं सभी दलों के सांसदों से हमारी नारी शक्ति के लिए इस महत्वपूर्ण कदम का समर्थन करने का आग्रह करता हूं। हम जिम्मेदारी और दृढ़ संकल्प के साथ इस दायित्व को पूरा करें। आइए, हम अपने लोकतंत्र की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

(लेखक भारत के पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

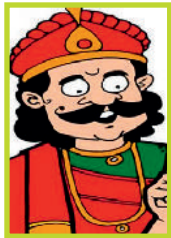
श्वास जीवन की पहली और आखिरी क्रिया



संकलित

दर्शन

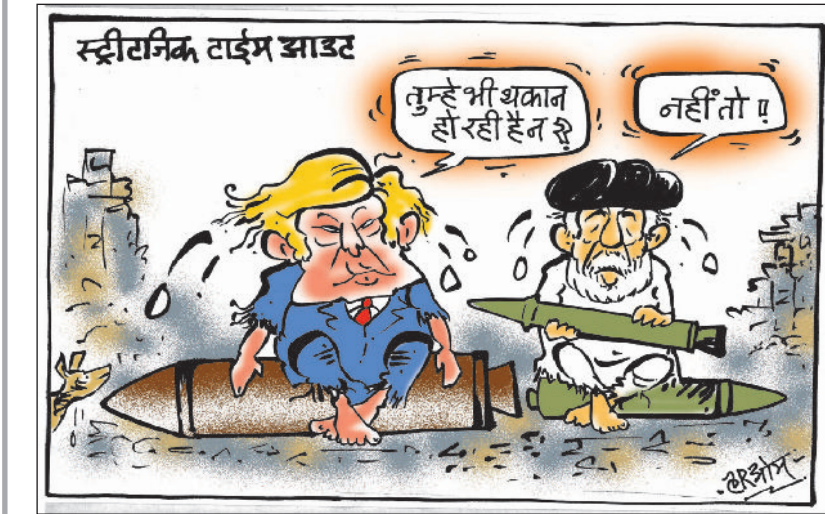
क्या आपने कभी गिना है कि एक मिनट में आप कितनी बार श्वास लेते हैं? श्वास जीवन की पहली और अंतिम क्रिया है। पूरे जीवन भर हम श्वास लेते रहते हैं, पर उस पर ध्यान नहीं देते। शरीर की लगभग 90 प्रतिशत अशुद्धियाँ श्वास से बाहर निकलती हैं, क्योंकि हम 24 घंटे श्वास लेते हैं, पर अपनी फेफड़ों की क्षमता का केवल 30 प्रतिशत ही उपयोग करते हैं। एक मिनट में हम लगभग सोलह-सत्रह बार श्वास लेते हैं। यदि आप चिंतित हैं तो यह बीस तक बढ़ सकती है, यदि आप क्रोध या अत्यधिक तनाव में हैं तो यह पच्चीस तक जा सकती है। शांत और प्रसन्न होने पर यह लगभग 10 रहती है और ध्यानवस्था में केवल दो-तीन श्वास प्रति मिनट। गहरा ध्यान श्वास की गति को अत्यंत धीमा कर देता है। मन पतंग के समान है और श्वास उसकी डोर। पतंग जितनी ऊंची उड़ानी हो, डोर उतनी लंबी चाहिए। यदि आप श्वास पर ध्यान देना सीख लें, तो किसी औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। श्वास अपार ऊर्जा प्रदान करती है और प्राणशक्ति को बढ़ाती है। ऊर्जा के चार स्रोत बताए गए हैं- भोजन, नींद, प्राणायाम (सुदर्शन क्रिया) और ध्यान में बिताए गए क्षण। इन सबका संतुलन समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। सुदर्शन क्रिया के लयबद्ध श्वास-प्रवाह से शरीर की विषाक्तता घटती है और मन में शांति बढ़ती है। शोध से यह प्रमाणित हुआ है कि सुदर्शन क्रिया रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है।



संकलित

प्रेरणा

अंतर्मन



करंट अफेयर

ग्रामीण भारत में 46% लोग भूमिहीन : रिपोर्ट

देश के ग्रामीण इलाकों में शीर्ष 10 प्रतिशत परिवारों के पास 44 प्रतिशत जमीन है, जबकि 46 प्रतिशत भूमिहीन हैं। ‘ वर्ल्ड इनइक्वैलिटी लैब’ के एक अध्ययन में यह बात कही गई है। ‘ भारत में भूमि असमानता : प्रकृति, इतिहास एवं बाजार’ शीर्षक वाले इस कार्य-पत्र में कहा गया है कि ग्रामीण भारत में शीर्ष पांच प्रतिशत परिवार 32 प्रतिशत जमीन के मालिक हैं, जबकि शीर्ष एक प्रतिशत परिवारों के पास 18 प्रतिशत कृषि भूमि है। यह अध्ययन नितिन कुमार भारती, डेविड ब्लेकस्ली और समरीन मरिड ने संयुक्त रूप से किया है। अध्ययन में करीब 65 करोड़ लोगों और 2.7 लाख गांवों के भूमि आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रामीण स्तर पर भूमि असमानता का औसत गिनी सूचकांक (0 से 100 के पैमाने पर) भूमिहीन परिवारों को शामिल करने पर 71 तक पहुंच जाता है जबकि 46 प्रतिशत ग्रामीण परिवार पूरी तरह भूमिहीन हैं। अध्ययन रिपोर्ट कहती है कि औसतन किसी गांव में सबसे बड़ा जमींदार लगभग 12 प्रतिशत जमीन नियंत्रित करता है, जबकि कुछ गांवों में एक ही व्यक्ति के पास आधे से अधिक कृषि भूमि है। राज्यों के बीच असमानता के स्तर में भी बड़ा अंतर देखा गया है, जो वैश्विक स्तर पर देशों के बीच पाए जाने वाले अंतर के लगभग बराबर है।



वेनट्रॉब ने 1993 में पहली बार बीपीएसएस की पहचान की थी। उन्होंने पाया था कि स्टोक से जुड़े गंभीर लक्षणों से जुड़ा रहे उनके कुछ मरीजों में ब्यूटी पार्लर या सैलून में बालों में शैंपू कराने के बाद ये समस्याएं उभरी थीं। स्ट्रोक एक तरह का मस्तिष्काघात है, जो मस्तिष्क में खून का प्रवाह घटने पर होता है। यह आमतौर पर मस्तिष्क में प्रमुख रक्त वाहिका में खून का थक्का जमने या उसके फटने के कारण होता है, जिससे कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, ग्लूकोज व अन्य पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं और वे दम तोड़ देती हैं।

विचार हरिभूमि 2

विचार

मानव धर्म ही सर्वोपरि

एक विदेशी को अपराधी समझ जब राजा ने फांसी का हुक्म सुनाया तो उसने अपशब्द कहते हुए राजा के विनाश की कामना की। राजा ने अपने मंत्री से, जो कई भाषाओं का जानकार था, पूछा- यह क्या कह रहा है? मंत्री ने विदेशी की गालियां सुन ली थीं, किंतु उसने कहा- महाराज! यह आपको दुआएं देते हुए कह रहा है- आप हजार साल तक जिएं। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन एक अन्य मंत्री ने जो पहले मंत्री से ईर्ष्या रखता था, आपर्पित उठाई- महाराज! यह आपको दुआ नहीं गालियां दे रहा है। वह दूसरा मंत्री भी बहुभाषी था। उसने पहले मंत्री की निंदा करते हुए कहा- ये मंत्री जिन्हें आप अपनी विश्वासपात्र समझते हैं, असत्य बोल रहे हैं। राजा ने पहले मंत्री से बात कर सत्यता जाननी चाही, तो वह बोला- हां महाराज! यह सत्य है कि इस अपराधी ने आपको गालियां दीं और मैंने आपसे असत्य कहा। पहले मंत्री की बात सुनकर राजा ने कहा- तुमने इसे बचाने की भावना से अपने राजा से झूठ बोला। मानव धर्म को सर्वोपरि मानकर तुमने राजधर्म को पीछे रखा। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। फिर राजा ने विदेशी और दूसरे मंत्री की ओर देखकर कहा- मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। निर्दोष होने के कारण ही तुम्हें इतना क्रोध आया कि तुमने राजा को गाली दी और मंत्री महोदय तुमने सच इसलिए कहा- क्योंकि तुम पहले मंत्री से ईर्ष्या रखते हो। ऐसे लोग मेरे राज्य में रहने योग्य नहीं। तुम इस राज्य से चले जाओ।



बिना गारंटी के ऋण

मोदी सरकार के नेतृत्व में, छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स को बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराकर, स्टरोजगार और लघु उद्योगों को नई शक्ति प्रदान की गई है। इस कर्यायाकारी योजना के तहत 40 लाख करोड़ से अधिक मूल्य के 58 करोड़ से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। -अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

किसानों का दर्द

किसानों का दर्द वही लोग सही मायने में समझ सकते हैं जिन्होंने स्वयं खेतों में पसीना बहाया हो। हमारा संकल्प है कि 2027 तक राजस्थान के हर जिले के किसानों को दिन के समय बिजली मिलेगी। -भजनलाल, सीएम, राजस्थान

चुनाव आयोग

अब यह कहने की भी जरूरत नहीं है कि चुनाव आयोग भागीप के इशारों पर काम कर रहा है और गाजपा से सीधे निर्देश ले रहा है। यह बात अब सबके सामने आ चुकी है और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। -अरविंद केजरीवाल, पूर्व सीएम, नई दिल्ली

युद्धविराम का स्वागत

अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच दो सप्ताह का युद्धविराम स्वागत योग्य कदम है। आशा है कि इन दिनों में समझौदारी से काम लिया जाएगा और हम स्थायी शांति की ओर बढ़ेंगे। वचो की सलाहनाओं से गहरा भविष्य मिलाना चाहिए, न कि दिनग्रा से। -कैलाश सत्यार्थी, नोबल पुरस्कार विजेता

हमारा पता

हरिभूमि कार्यालय

रिंग रोड नं. 2, गौरवपथ, बिलासपुर
फ़ोन : 401050,271016,फैक्स-271018
ई-मेल : haribhoomibsp@gmail.com
वेब-साइट : www.haribhoomi.com

गणनात्मक विचार होगा सिलेबस का हिस्सा, छात्र जानेंगे-कैसे काम करता है इंस्टाग्राम व यूट्यूब का एल्गोरिद्म

हरिभूमि न्यूज़ ►► रायपुर

सीबीएसई संबद्ध स्कूलों में अब ब्लैकबोर्ड की जगह व्हाइटबोर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरी कक्षा से दसवीं कक्षा तक के लिए एआई और कम्प्यूटेशनल थिंकिंग का नया कोर्स शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा एनसीईआरटी और सीबीएसई मिलकर क्षेत्रीय भाषाओं में भी पढ़ाई कराएंगे। सीबीएसई के अनुसार, रबन की प्रवृत्ति के स्थान पर अब जोर इस पर होगा कि बच्चा कितना बेहतर सोच सकता है और कैसे नई चीजें

छात्रों की मातृभाषा में सिखाई जाएगी कोडिंग और डेटा एनालिसिस सरल विधि से सिखाएंगे गणित, ताकि अपग्रेड हो सकें विद्यार्थी



डिजाइन कर सकता है। इस बड़े बदलाव का सबसे खास हिस्सा यह है कि अब टेक्नोलॉजी की पढ़ाई केवल गणित विषय में ही नहीं होगी। एन सी ई आर टी और सीबीएसई मिलकर ऐसा सिलेबस तैयार कर रहे हैं, जिसे स्टूडेंट्स अपनी मातृभाषा में पढ़ और समझ सकेंगे। चाहे कोडिंग हो या डेटा एनालिसिस, छात्र अपनी भाषा में दुनिया की आधुनिक तकनीक सीख सकेंगे। सीबीएसई नए सिलेबस से ढाई का तरीका बदलने के साथ छात्रों को अपग्रेड करने की तैयारी कर रहा है।

गौरतलब है, तीसरी से आठवीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स के लिए कम्प्यूटेशनल थिंकिंग अर्थात गणनात्मक विचार और एआई को सिलेबस का हिस्सा बना दिया गया है। फिलहाल इसे 6वीं से 8वीं तक लागू किया जा रहा है और अगले साल से 9वीं-10वीं के छात्र भी इसे पढ़ेंगे। इसे किसी अलग मुश्किल विषय की तरह नहीं, बल्कि गणित के साथ जोड़कर पढ़ाया जाएगा। इससे गणित का डर खत्म होगा और छात्र डेटा को सरलता से समझ सकेंगे।

सिखाएंगे वैज्ञानिक की तरह सोचना

बोर्ड के अनुसार, विद्यार्थियों के संदर्भ में अक्सर यह शिकायत आती है कि वे परीक्षा के लिए रट्टा मारते हैं और बाद में सब भूल जाते हैं। इसका हल ढूँढते हुए अब पूरा फोकस किटिकल थिंकिंग पर किया जा रहा है। अर्थात बच्चों को सवाल हल करने के लिए मशीन जैसा नहीं, बल्कि वैज्ञानिक जैसा सोचना सिखाया जाएगा। छात्र यह समझ सकेंगे कि मोबाइल में जो एल्गोरिद्म चल रहा है, वो काम कैसे करता है। इससे वे तकनीक के गुलाम नहीं, बल्कि उसके निर्माता बन सकेंगे।

भाषायी ज्ञान के अभाव में पिछड़े

कई बार बच्चे सिर्फ इंग्लिश पीछे रह जाते थे क्योंकि टेक्नोलॉजी से जुड़े भारी-भरकम शब्द अंग्रेजी भाषा में होते थे। आज-कल के बच्चे सोशल मीडिया पर बहुत वक्त बिताते हैं। नए सिलेबस में बच्चों को सिखाया जाएगा कि इंस्टाग्राम या यूट्यूब के पीछे का एल्गोरिद्म उन्हें कैसे चीजें दिखाता है। इससे स्टूडेंट्स में डेटा की समझ बढ़ेगी और वे सोशल मीडिया का सही और सुरक्षित इस्तेमाल कर सकेंगे। सीबीएसई स्कूलों में अब ऐसी पढ़ाई पर जोर दिया जाएगा जो सीधे भविष्य की नौकरियों और जरूरतों से जुड़ी हो।

खबर संक्षेप

मिठाई कारखाने में गंदगी, लगा 10 हजार ई-जुर्माना

रायपुर। नगर निगम जोन-2 के स्वास्थ्य विभाग ने रमन मंदिर वार्ड स्थित मिठाई कारखाने में गंदगी मिलने की जनशिकायत सही पाए जाने पर संचालक लोकेश खत्री पर तत्काल 10 हजार रुपए का ई-जुर्माना लगाया। कारखाना संचालक को चेतावनी दी गई कि दोबारा ऐसा हुआ तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी। नगर निगम आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर जोन कमिश्नर संतोष पांडे के मार्गदर्शन में जोन स्वास्थ्य अधिकारी रवि लावनिया की उपस्थिति में जोन-2 के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिठाई कारखाने की स्वच्छता व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वहां गंदगी मिली। जनशिकायत सही पाए जाने पर जोन-2 कमिश्नर के निर्देश पर जोन स्वास्थ्य अधिकारी ने कारखाना संचालक पर 10 हजार रुपए ई-जुर्माना किया।

जल जीवन मिशन अंतर्गत नल जल मित्र कार्यक्रम के तहत जल वितरण संचालन-संधारण के लिए दी गई थी ट्रेनिंग

मुख्यमंत्री कौशल योजना में 120 युवाओं ने ली ट्रेनिंग, आदेश के बाद भी मिली नहीं नौकरी

हरिभूमि न्यूज़ : रायपुर

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लाईवलीहुड कॉलेज से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले जिले के सैकड़ों युवा रोजगार पाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं। इनमें 120 युवा ऐसे हैं, जो जल जीवन मिशन अंतर्गत नल जल मित्र कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। उनके प्रशिक्षण के आधार पर ही ग्राम पंचायतों में जल वितरण के संचालन और संसाधन कार्य के लिए उनका चयन भी हुआ है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने इसके लिए ग्राम पंचायतों को पत्र भी जारी किया था, जिसमें चयनित युवाओं को पंचायत स्तर पर मानदेय के आधार पर नौकरी पर रखने के लिए अनुशंसा की गई थी। इसके बावजूद इन युवाओं को अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इन युवाओं ने संबंधितों को ज्ञापन सौंपा है।

जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत ग्राम पंचायतों में हर घर नल कनेक्शन, पानी टंकी का निर्माण हुआ है। इसके तहत जिन ग्रामों में ये कार्य पूर्ण हो चुके हैं, उन ग्रामों में पानी टंकी से जलप्रदाय करने एवं उसके संसाधन के लिए अनुभवी लोगों की जरूरत थी। इसके लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत लाईवलीहुड कॉलेज में युवाओं को नल-जल मित्र कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के बाद



आवश्यकता के अनुसार जिले के चारों ब्लॉक धरसीवा, आरंग, अमनपुर एवं तिल्व के लगभग 120 युवाओं को विभिन्न गांव में जलप्रदाय एवं संधारण कार्य के लिए चयन हुआ। इन चयनित युवाओं के माध्यम से ग्राम पंचायतों में जलप्रदाय एवं संधारण का कार्य हो, इसके लिए पीएचई विभाग ने चयनित गांव के सरपंचों को नियुक्त करने के लिए अनुशंसा पत्र भेजा था। इस अनुशंसा पत्र के अनुसार 12 हजार रुपए मासिक वेतन पर युवाओं की अस्थायी रूप से नियुक्ति होनी थी, जो अब तक नहीं हो पाई है। प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं ने बताया कि नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद भी ग्राम पंचायतों में नौकरी नहीं मिलने पर वे सभी पीएचई विभाग के अफसर अनिल बच्चन से मिलने गए थे, लेकिन उन्होंने यह कहकर उन्हें लौटा दिया कि 45 दिन की

ट्रेनिंग करने से नौकरी थोड़े ही मिल जाती है। उनके इस रवैये के बाद ही अब वे सभी जिला पंचायत उपाध्यक्ष और सीईओ के समक्ष गुहार लगाने पहुंचे।

सरपंचों में किसी ने कहा- वेतन बहुत ज्यादा, किसी ने कहा, पीएचई विभाग देगा

हरिभूमि ने कुछ सरपंचों से भी नियुक्ति नहीं करने के संबंध में बातचीत की। इस दौरान ग्राम पंचायत कोटा के सरपंच ने कहा कि वेतन बहुत ज्यादा है। हमारे पास इतना फंड नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 हजार ही दे पाएंगे। ग्राम पंचायत सोनतरा के सरपंच ने कहा कि वेतन पीएचई विभाग को ही देना है। इस संबंध में आदेश भी जारी हुआ था। ग्राम पंचायत में इतना फंड नहीं रहता कि इस कार्य के लिए 10-15 हजार रुपए मासिक वेतन दे पाएं।

रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इन सभी युवाओं को ग्राम पंचायतों में रोजगार देने की व्यवस्था करनी चाहिए।

- संदीप यदु, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत रायपुर

**साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड**
“मिनी रल कम्पनी”
(कोल इण्डिया लिमिटेड का उपक्रम)

सार्वजनिक सूचना / जनसूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम मदननगर, कनकनगर एव जगन्नाथपुर, तहसील - प्रतापपुर, जिला - सुरजपुर (छ.ग.) और ग्राम चौरा तहसील - राजपुर जिला - बलरामपुर & रामानुजगंज (छ.ग.) स्थित भूमि, रकबा 1937.202 हेक्टेयर, का अधिग्रहण CBA Act 1957 की धारा 9(i) के तहत SECL, भटगांव क्षेत्र द्वारा मदननगर खुली खदान परियोजना हेतु दिनांक 20/11/2023 को किया जा चुका है।
उक्त अधिग्रहित भूमि पर प्रस्तावित मदननगर खुली खदान परियोजना हेतु DGPS सर्वे का कार्य को SECL भटगांव क्षेत्र द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।
किन्तु यह देखा गया है कि कुछ स्थानीय ग्रामीणों/व्यक्तियों द्वारा बिना किसी वैधानिक अधिकार के उक्त सर्वे कार्य में अनावश्यक बाधा उत्पन्न की जा रही है तथा सर्वे टीम को कार्य करने से रोकता जा रहा है। इस प्रकार की गतिविधि शासकीय कार्य में अवरोध की श्रेणी में आता है।
अतः सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम सूचित किया जाता है की उक्त भूमि का अधिग्रहण विधि अनुसार पूर्ण किया जा चुका है। DGPS सर्वे शासकीय एवं वैधानिक प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। सर्वे कार्य में किसी प्रकार का अवरोध कानूनन दंडनीय होगा।
यदि किसी व्यक्ति को उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई दावा/आपत्ति हो तो वे अपने वैध दस्तावेजों सहित सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी के सक्षम प्रस्तुत करें। अन्यथा, भविष्य में उत्पन्न किसी प्रकार की विधिक कार्यवाही हेतु सम्बंधित व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होंगे।
दिनांक - महाप्रबंधक, एसईसीएल भटगांव क्षेत्र

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कैबियट आवेदन क्रमांक _____ / 2026
WPC क्रमांक _____/2026

कैबियटर : साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(प्रस्तावित प्रतिवादी) महाप्रबंधक, भटगांव क्षेत्र के माध्यम से
बनाम

नॉन-कैबियटर : आम जनता / सभी संबंधित व्यक्ति
(प्रस्तावित याचिकाकर्ता/गण) जिन्हें यह संबंधित हो सकता है

दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 148-A के अंतर्गत कैबियट उपरोक्त नामित कैबियटर निम्नानुसार निवेदन करता है :

1. कि कैबियटर, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL), ग्राम मदननगर, कनकनगर, जगन्नाथपुर (तहसील - प्रतापपुर, जिला - सुरजपुर, छत्तीसगढ़) एवं ग्राम चौरा (तहसील - राजपुर, जिला - बलरामपुर - रामानुजगंज, छत्तीसगढ़) में स्थित एक ओपन-कास्ट कोयला खनन परियोजना संचालित कर रहा है। उक्त परियोजना के लिए लगभग 1937 हेक्टेयर भूमि केंद्र द्वारा अर्जित की गई थी, जिसे तत्पश्चात् उक्त अधिनियम की धारा 1(i) के अंतर्गत दिनांक 16.02.2024 को खनन कार्यों हेतु कैबियटर को आवंटित/सौंपा गया। दिनांक 16.02.2024 की अधिसूचना की प्रति संलग्नक अनुलग्नक C-1 के रूप में संलग्न की गई है।

2. कि कैबियटर को परियोजना के प्रारंभ हेतु DGPS सर्वे तथा अन्य प्रारंभिक गतिविधियाँ संचालित करना आवश्यक है। और कैबियटर को ज्ञात हुआ है तथा उसे आशंका है कि कुछ निजी व्यक्ति/लोग/समूह/लोगों के समूह या पंजीकृत/अपंजीकृत समूह कैबियटर के उपर्युक्त उत्तिखित कार्यों को चुनौती दे सकते हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका के माध्यम से अथवा जनहित याचिका दाखल करके इस माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, जिसमें SECL द्वारा की गई उक्त कार्यवाही की वैधता, निष्पक्षता या औचित्य को चुनौती देने अथवा SECL द्वारा प्रारंभ की गई उक्त कार्यवाही को रोकने या रद्द करने तथा अंतरिम राहत/स्वामन हेतु आवेदन के साथ अनुरोध किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, 'चेतन सिंह चौहान, अधिवक्ता, R-9/21 रामा वैली, बोंदरी बिलासपुर (C.G.), संपर्क: 8280810559' को सूचना दी जाए, ताकि कैबियटर के हित की समुचित रक्षा की जा सके।

3. कि इस कैबियट की सूचना की प्रति क्षेत्र में प्रसारित समाचार पत्र में प्रकाशित की गई है। उक्त प्रकाशन की समाचार-पत्र कटिंग की प्रति संलग्नक अनुलग्नक C-2 के रूप में संलग्न की गई है।

प्राप्तर्ना

कैबियटर अत्यंत सविनय प्रार्थना करता है कि यह माननीय न्यायालय इस कैबियट को अभिलेख पर लेने की कृपा करे और SECL की उक्त कार्यवाहियों से संबंधित किसी भी प्रकरण में कैबियटर को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना कोई एकपक्षीय या अंतरिम आदेश पारित न करे।

बिलासपुर (C.G.)
दिनांक : . 2026

(चेतन सिंह चौहान)
कैबियटर/प्रस्तावित
प्रतिवादी के अधिवक्ता

आई-गॉट में सभी विभागों को ऑन-बोर्ड होना जरूरी

हरिभूमि न्यूज़ : रायपुर

मुख्य सचिव विकासशील ने राज्य शासन के सभी विभाग के प्रमुख अधिकारियों से कहा है कि वे मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आई-गॉट ट्रेनिंग कार्यक्रम से अपने विभाग को अनिवार्य रूप से ऑन-बोर्ड कर लें। उन्होंने कहा, सभी विभाग ऑन-बोर्ड हो जाएं। मुख्य सचिव ने सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों को भी अपने मोबाइल के माध्यम से ऑन-बोर्ड होने को कहा है। राज्य शासन के सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों को उनकी आवश्यकतानुसार विभागीय रिकल डेवलपमेंट के लिए प्रशिक्षित किया जा सकेगा। मुख्य सचिव ने सभी विभाग प्रमुखों से कहा है कि वे अपने-अपने विभाग की आवश्यकता के अनुसार अधिकारी-कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कोर्स तय कर लें, जिससे उन्हें प्रशिक्षित किया जा सके।

आई-गॉट प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत साधना सप्ताह के मौके पर सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारी को कर्मयोगी मिशन के तहत प्रशिक्षण देने कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में राज्य शासन के विभागों के प्रमुख अधिकारी सहित विभागीय सचिव, संयुक्त सचिव, उपसचिव, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में सभी जिलों के प्रमुख अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए।

आधी आबादी की अनदेखी करना तानाशाही

हरिभूमि न्यूज़ : रायपुर

आगामी डिजिटल जनगणना के अंतर्गत 16 अप्रैल से 30 मई तक भौतिक सत्यापन के लिए निर्धारित 33 बिंदुओं में अन्य ओबीसी वर्ग के लिए अलग से कॉलम नहीं होने पर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जताई है। आप आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष उत्तम जायसवाल ने बुधवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सरकार ओबीसी वर्ग के लिए दोहरा मापदंड अपना रही है। मंडल आयोग (1980) के अनुसार देश में ओबीसी की आबादी 52% बताई गई थी। देश की आधी आबादी की अनदेखी समझ से परे है। पिछड़े समाज के विकास की बात करने वाली केंद्र और राज्य सरकार इस मामले में असहाय क्यों नजर आ रही है। सरकार पिछड़ों को सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखना चाहती है। राजपत्र के बिंदु क्रमांक 12 में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए स्पष्ट कॉलम दिया गया है, लेकिन ओबीसी वर्ग की गणना के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र चंद्रकार ने कहा कि एक ओर केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराने की घोषणा करती है, तो दूसरी ओर राजपत्र से ओबीसी का कॉलम नहीं रखना समाज के साथ अन्याय है। बिना पृथक कॉलम के ओबीसी वर्ग की सही संख्या कैसे सामने आएगी। पिछड़ों को उनके अधिकार से वंचित रखने की सरकार की साजिश है। भारत देश एकता और सामाजिक समरसता का प्रतीक है, जिसे केंद्र की भाजपा सरकार मिटाने पर तुली हुई है। प्रदेश सचिव अनुषा जोसेफ, पलविंदर सिंग पन्नु, शकील खान ने भी इस पर आपत्ति जताई।

यादव समाज के उत्थान और विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर की चर्चा

रायपुर। कमल विहार रायपुर स्थित त्रिपुर यात्रा सेवा समिति के समारोह में रविवार को छत्तीसगढ़ यादव शासकीय सेवक संघ की उप-समिति, एकादश उत्थान यादव कल्याण संघ की बैठक हुई। बैठक में समाज के उत्थान और विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य वक्ता सुरेश कुमार यादव ने संघ के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए समाज के प्रत्येक परिवार से न्यूनतम 11 रुपए प्रतिमाह सहयोग राशि देने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि 10 लाख परिवारों के इस छोटे-से योगदान से एक बड़ी सामाजिक पहल को मूर्त रूप दिया जा सकता है।

**MARUTI SUZUKI ARENA**

**VICTORIS**
INDIAN CAR OF THE YEAR 2026

**ICOTY**
INDIAN CAR OF THE YEAR 2026

**LOYALTY REWARD OF UP TO ₹30,000 ON EXCHANGE OF MARUTI SUZUKI CARS****

LEVEL 2 ADAS WITH 10+ FEATURES

DOLBY ATMOS SPATIAL SOUND EXPERIENCE

SMART POWERED TAILGATE WITH GESTURE CONTROL

64-COLOUR AMBIENT LIGHTING

AVAILABLE IN STRONG HYBRID

SCAN AND CONNECT TO A SHOWROOM NEAR YOU

E-BOOK TODAY AT WWW.MARUTISUZUKI.COM

CONTACT US AT 1800-102-1800

ICOTY Partner Media

Rutube | autoX | Cx | CarDekho | carwale | eva | MOTORING | OZORNET | ThePrint | turbocharged

Applicable T&C available at your nearest dealership. Creative visualization. Car colour may vary due to printing on paper. Images used are for illustration purposes only. ADAS features are for driver assistance only. Driver is responsible for safe and attentive driving. Features may vary by model/conditions. For details on functioning of safety features including airbags, kindly refer to the Owner's Manual. Trademarks/logos being displayed belong to the respective owners. Infinity is the trademark of HARMAN International Industries Incorporated. Dolby Audio, Dolby Atmos and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Amazon, Alexa and all related marks are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. *Price for ex-showroom Delhi for Lxi (Petrol Variant) is ₹10.49 900/- **The loyalty reward scheme is subject to terms and conditions. For more details visit authorised dealership. The offer is valid only on Victoris.

VICTORIS

हाईकोर्ट ने करंट से हाथियों की मौत मामले में एसीएस से शपथ पत्र साथ मांगा जवाब

हरिभूमि न्यूज़, बिलासपुर

प्रदेश में लगातार बिजली करंट से हाथियों की मौत घटना मामले को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि उपरोक्त घटनाएं किन परिस्थितियों में हुईं और विभाग द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 5 मई को निर्धारित की गई है।

छत्तीसगढ़ में लगातार बिजली करंट से हो रही हाथियों की मौत की घटनाओं को चीफ जस्टिस ने गंभीरता से लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई प्रारंभ की है। बुधवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में जनहित याचिका की सुनवाई हुई। याचिका में हस्तक्षेपकर्ता रायपुर निवासी नितिन सिंघवी की तरफ से कोर्ट में मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि 12 मार्च को दो हाथी शावकों की करंट लगने से रायगढ़ जिले के घरघोड़ा वन परिक्षेत्र में मौत हो गई। 14 मार्च को सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में खेत में करंट का तार लगाने से एक हाथी की मौत हो गई। मार्च में ही सारंगढ़ बिलाईगढ़ में जंगली सूअर के शिकार के लिए लगाए गए अवैध बिजली करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। 26 मार्च को मैनपाट क्षेत्र में जंगली जानवरों के शिकार के लिए बिछाए गए तरंगित तार की चपेट में आने से एक युवक और एक लोमड़ी की मौत हो गई। कोरबा के सकोदा जंगल में 11 केवी करंट प्रवाहित तार की चपेट में आने से दो शावक सहित मादा भालू की मौत हो गई। हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि उपरोक्त घटनाएं किन परिस्थितियों में हुईं और विभाग द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। जनहित याचिका की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 5 मई की तिथि निर्धारित की है।

शासन को जल्द

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने तखतपुर नगर के पुराने हास्पिटल को नगर से सात किमी दूर लिंदरी गांव में स्थानांतरित किए जाने के जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शासन को जल्द स्वीकृति प्राप्त कर हास्पिटल प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं।

हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ शासन को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह जल्द स्वीकृति प्राप्त कर तखतपुर नगर के पुराने हास्पिटल भवन में हास्पिटल प्रारंभ करें ताकि नगर की जनता को त्वरित इलाज मिल सकें। ज्ञात हो कि तखतपुर नगर के 50 वर्षों से भी ज्यादा पुराने सरकारी हास्पिटल को स्वास्थ्य विभाग ने उक्त जनहित याचिका में अपने बचाव में जवाब देकर नगर से 7 किलोमीटर दूर लिंदरी गांव में स्थानांतरित करा दिया है। इससे नगर की जनता खासकर गरीब जनता को ईलाज

पुलिस को चकमा देकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने असम के मुख्यमंत्री सरमा का पुतला फूँका

रायपुर। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने जोरदार प्रदर्शन किया। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी चौक के पास एकत्रित होकर असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने पुतला दहन रोकने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रणनीति के तहत पहले एक पुतला जलाया, जिसे पुलिस ने छीन लिया।

राशिफल

	वस्त्रों के प्रति रुझान बढ़ सकता है। रहन-सहन अद्यवस्थित रहेगा। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में लाभ के अवसर बढ़ेंगे।
मेघ	आशा-निराशा के भाव रहेंगे। व्यर्थ के क्रोध एवं वाद-विवाद से बचें। परिश्रम भी अधिक रहेगा। लाभ के अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
वृष	आत्मविश्वास तो बहुत रहेगा, परन्तु मन परेशान हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। खर्चों की अधिकता रहेगी। सुस्वादु खानपान में रुचि रहेगी।
मिथुन	मन में उतार-चढ़ाव रहेगा। धर्म के प्रति श्रद्धाभाव रहेगा। कारोबार में कठिनाइयाँ आ सकती हैं। सचेत रहें। कारोबार में परिश्रम भी अधिक रहेगा।
कर्क	आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे, परन्तु आत्मसंयत भी रहें। वैयर्थीलता बनाये रखने के प्रयास करें। धार्मिक संगीत में रुचि बढ़ सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
सिंह	पठन-पाठन में रुचि रहेगी। शैक्षिक कार्यों के लिए विदेश जा सकते हैं। लेखनादि-बौद्धिक कार्यों में मान-सम्मान की प्राप्ति होगी।
कन्या	आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा, परन्तु वैयर्थीलता में कमी हो सकती है। कारोबार में वृद्धि होगी। शैक्षिक कार्यों के लिए किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं।
तुला	मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। शासन-सत्ता का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता के योग हैं।
वृश्चिक	व्यर्थ के क्रोध एवं वाद-विवाद से बचें। नौकरी में अफसरों से सद्भाव बनाकर रखें। जीवनसाथी से मतभेद हो सकते हैं।
धनु	मन प्रसन्न तो रहेगा, परन्तु वैयर्थीलता बनाये रखने के प्रयास करें। नौकरी में अफसरों का सहयोग तो मिलेगा, परन्तु स्थान परिवर्तन भी हो सकता है।
मकर	स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। चिकित्सीय खर्च बढ़ सकते हैं। कारोबार में परिश्रम अधिक रहेगा। कुछ कठिनाइयां भी आ सकती हैं।
कुंभ	शैक्षिक कार्यों में मन लगेगा। खर्चों की अधिकता रहेगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। रहन-सहन अद्यवस्थित रहेगा।
मीन	

जेलों में 33 कैदियों की मौत मामले में डीजी से मांगा हलफनामा

जेलों में 33 कैदियों की मौत मामले में डीजी से मांगा हलफनामा

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के जेलों में एक साल भीतर 33 कैदियों की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए जेल महानिदेशक से हलफनामा मांगा है। अधिकांश मौतें बीमारी या हृदय, गुर्बां खराब होने के कारण बताई गई हैं। लेकिन 22 मामलों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट लंबित है। इस मामले में अगली सुनवाई 15 अप्रैल तय की गई है। हाईकोर्ट ने कैदियों की बढ़ती मौतों पर गंभीर चिंता जताई है। जेल महानिदेशक के हलफनामे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देरी और आरोपों की गंभीरता का उल्लेख किया गया है। इसी बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी जेल में हुई मौतों और चिकित्सा सुविधाओं पर विस्तृत रिपोर्ट की मांग की है, जिससे राज्य में हिरासत की स्थितियों में हो रही मौत की जांच तेज हो गई है। हाईकोर्ट ने विभिन्न जेलों में कैदियों की मृत्यु दर में वृद्धि दर्शाने वाली रिपोर्ट की स्वतः संज्ञान में लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई प्रारंभ की है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल ने

हाईकोर्ट ने रायपुर बार एसोसिएशन चुनाव पर लगाई रोक

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने 17 अप्रैल को होने जा रहे रायपुर बार एसोसिएशन चुनाव में पुरुषों को दिए गए 50 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ पेश याचिका पर सुनवाई के बाद पूरे चुनाव पर रोक लगा दी है। जस्टिस नरेश कुमार चन्द्रवंशी ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के बायलाज में पुरुष आरक्षण की जानकारी मांगी, प्रतिवादी ऐसा कोई प्रावधान नहीं बता सके। इसके बाद कोर्ट ने बार चुनाव पर स्थगन आदेश जारी किया है। रायपुर बार एसोसिएशन का चुनाव 17 अप्रैल को होना है। इस चुनाव को लेकर निर्वाचन अधिकारी ने पुरुषों के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित कर दिए हैं। इससे एक नया विवाद खड़ा हो गया और रायपुर की महिला अधिकरता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस मामले में पेरवी कर रही अधिकरता हमीदा सिद्दीकी ने कोर्ट को बताया कि संविधान में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के विदेशकुमार योगमाया मामले 30 प्रतिशत का आरक्षण निर्धारित किया गया है। व्याय के क्षेत्र में महिलाएं भी योगदान देती है प यहां महिलाओं के आरक्षण को छोड़ पुरुषों को 50 प्रतिशत आरक्षण दे दिया गया है। इस पर पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए निर्देश दिया था कि पुरुषों को दिए गए इस आरक्षण को तत्काल हटाय़ा जाए नहीं तो कल ही सुनवाई में इस पर रोक लगा दी जाएगी। बताया गया कि जिला अधिवक्ता संघ रायपुर का कार्यकाल गत जनवरी 2026 को खत्म हो गया था। इसके बाद पूर्व पदाधिकारी ने व्हाट्सएप ग्रुप में ही सहायक निर्वाचन अधिकारी और अपीलीय समिति बनाई गई। कोई सामान्य सभा नहीं बुलाई गई और 23 मार्च को प्रक्रिया पूरी कर ली गई। 24 मार्च को अधिसूचना जारी कर पुरुषों को नियमों के विपरित 50 प्रतिशत आरक्षण दे दिया।

हास्पिटल प्रारंभ करने दिए निर्देश



के लिए अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे क्षुब्ध होकर नगर पालिका के पार्षद द्वय मुन्ना श्रीवास व

नगरीय निकायों के माध्यम से आश्रम-छात्रावासों के सेंटिक टैकों की हो सफाई

बजट का उपयोग नहीं कर पाए, चार जिलों के सहायक आयुक्त को शोर्काँज नोटिस

हरिभूमि न्यूज़ : रायपुर
आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विभागीय योजनाओं, आय-व्यय तथा आगामी कार्ययोजनाओं सहित विभिन्न विकास कार्यों की गहन समीक्षा की गई। प्रमुख सचिव ने विभागीय योजनाओं में बेहतर कार्य करने वाले जिलों की सराहना की, वहीं विभिन्न मंर्यों के बजट आवंटन का सदुपयोग न करने वाले चार जिले बलोदाबाजार-भाटापारा, बमेतरा, जशपुर और बिलासपुर के सहायक आयुक्तों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी शैक्षणिक सत्र को ध्यान में रखते हुए आश्रम छात्रावासों की व्यवस्थाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। छात्रावासों में अग्निशमन यंत्र और सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने “प्रोजेक्ट संकल्प” के तहत विद्यार्थियों के सांस्कृतिक, मानसिक एवं नैतिक विकास को और मजबूत करने के लिए ध्यान और योग को भी शामिल करने की बात कही। इसके अलावा सेप्टिक टैंकों की सफाई मैनुअल तरीके से न कराकर, नगरीय निकायों के माध्यम से सक्शन मशीनों से कराने के निर्देश दिए। बैठक में छात्रवृत्ति योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर संतोष जताया गया। बताया गया कि नई व्यवस्था के तहत

शब्द पहेली - 6190						
1	2		3	4	5	6
						7
8				9		10
			11		12	13
14					15	16
				17	18	19
			20	21	22	23
				24	25	
			26			
27		28			29	
		30	31		32	
33	34		35			36
					37	
37				38		

1. पवनपुत्र, हनुमान-3,3
5. मजार-4
8. बगौचा (अंग्रेजों में-2)
9. तहजीब, तमोज-3
10. सत्य, तेज-2
11. पतंगा-4
12. इंसॉई साध्वी-2
14. इंकार करना-4
16. उत्तम, आदर्शवादी-3
18. रोमांच, उद्देग-4
20. पागलपन, सनक-5
23. पालन-पौषण-5
26. आनंद लेना-2,2
27. बेईमानी, अमानत में खमानत-3
29. अप्रथमान, गौण-4
30. ठाठ-बाट-2
31. अति काला, एक प्रसार की लकड़ी-4
33. रहस्य-2
35. गरुड़ जो राखण से

महानिदेशक कारागार को इस मामले में व्यवतगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट के अनुसार बिलासपुर केन्द्रीय जेल में सबसे अधिक 10 मौतें दर्ज की गईं। दुर्ग जेल में 8 मौतें और अंबिकापुर जेल में 5 मौतें तथा जगदलपुर एवं गरियाबंद में 2-2 कैदियों की मौत दर्ज की गईं। धमतरी, बलरामपुर, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़ और कांकेर से एक-एक कैदियों की मौत हुई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बीमार पड़ने पर इनमें से कई कैदियों को छत्तीसगढ़ चिकित्सा विज्ञान संस्था सिन्ध बिलासपुर या डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल रायपुर में भर्ती कराया गया था लेकिन वे बच नहीं पाए। कोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने में देरी को लेकर नाराजगी जताई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पिछले दो वर्षों में कैदियों की मृत्यु के संबंध में मुख्य सचिव और महानिदेशक जेल से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने कैदियों को उपलब्ध कराई गई चिकित्सा सुविधाओं पर भी सवाल उठाए हैं।

किराए के पानी टैंकर चलाने आधा दर्जन ठेकेदारों ने भरी निविदा, दस्तावेज परीक्षण के बाद ठेका

गुरुवार को तय होगी प्रति ट्रिप टैंकर किराए की दर, वार्डवार मंगाई सूची, टैंकर के लिए तय होंगे

हरिभूमि न्यूज़ : रायपुर

शहर को टैंकर मुक्त करने का फंडा इस बार भी फिक्स हो गया है। नगर निगम के जल विभाग ने गमीं के सीजन को देखते हुए जलसंकट प्रभावित इलाकों में

■ पिछले बार 495 रुपए प्रति ट्रिप की दर, इस बार 50 रुपए बढ़ सकती है
--

किराये के टैंकर से पानी आपूर्ति के लिए ऑनलाइन टेंडर किया है। इस टेंडर में आधा दर्जन ठेकेदारों ने दिलचस्पी लेते हुए भाग लिया। बुधवार को संबंधित ठेकेदारों के लिफाफे खोलकर दस्तावेज परीक्षण किया जा रहा है। गुरुवार

को सबसे कम रेट कोड करने वाली ठेका एजेंसी को ट्रिप के आधार पर किराए के पानी टैंकर चलाने का जिम्मा सौंपा जाएगा। पिछले साल की गमीं में प्रति ट्रिप किराए के टैंकर की दर 495 रुपए तय की गई थी, इस बार डीजल-पेट्रोल के बढ़े दामों को देखते हुए प्रति ट्रिप टैंकर किराए की दर बढ़कर 525 रुपए तक होना अनुमानित है। जल विभाग ने महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर जल विभाग अध्यक्ष संतोष-सीमा साहू के साथ मिलकर नगर निगम के दस जोन से जलसंकट संभावित क्षेत्रों की वार्डवार सूची मंगाई है। साथ ही किस क्षेत्र में कितने पानी टैंकर की जरूरत होगी, कौन-कौन से संभावित इलाके पाईंट के रूप में बनाए जाएंगे, इसके लिए वार्ड पार्षदों के माध्यम से जानकारी ली जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, किराए के पानी टैंकर आउटर के वाडों में चलाए जाएंगे। प्रति ट्रिप दर तय होते ही संबंधित जोन से वर्कआर्ड

युद्ध विराम संग छात्रों का मूल्यांकन प्रारंभ

हरिभूमि न्यूज़ : रायपुर
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पश्चिमी एशिया के उन देशों के कक्षा 12 छात्रों के लिए वैकल्पिक मूल्यांकन योजना के तहत अंक अपलोड करने का शेड्यूल जारी कर दिया है, जहां बोर्ड परीक्षाएं भू-राजनीतिक परिस्थितियां अर्थात युद्ध के कारण रद्द कर दी गई थीं। यह निर्णय प्रभावित छात्रों के रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए लिया गया है। सीबीएसई द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, स्कूलों के लिए ऑनलाइन पोर्टल 8 अप्रैल से 17 अप्रैल 2026 तक खुला रहेगा। इस दौरान संबंधित स्कूल अपने लॉगिन के माध्यम से छात्रों के अंक अपलोड कर सकेंगे। बोर्ड ने निर्देश दिया है कि सभी स्कूल नोटिफिकेशन-2 को ध्यान से पढ़ें और उसी के अनुसार प्रक्रिया पूरी करें। सीबीएसई ने साफ कहा है कि अंक अपलोड करते समय अत्यधिक सावधानी बरती जाए, क्योंकि बाद में किसी भी प्रकार की

गलती या संशोधन के लिए अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने भी समयसीमा का पालन करने पर जोर दिया है। सीबीएसई ने 16 मार्च से 10 अप्रैल 2026 के बीच होने वाली कक्षा 12 की परीक्षाएं बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे वेस्ट एशियाई देशों में रद्द कर दी थीं। यह फैसला वहां की असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया था। नई नीति के तहत छात्रों का रिजल्ट इंटरनल असेसमेंट और 28 फरवरी 2026 तक हुई परीक्षाओं के प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया जाएगा।

OFFICE OF MUNICIPAL CORPORATION KORBA			
e-Procurement Tender Notice Main Portal: http://eproc.cgstate.gov.in			
NIT No :1508/WS/2026		Korba Dated 01.04.2026	
Sr No.	System Tender No.	Name of Work/Description of Work	Probable Amount of Contract
	1	188277 (1st Call) Interconnection work from main pipe line to distribution pipe line (DI/GI) near dhyan chand chowk and darri barrage near pragati nagar	26.93 Lacs
The details can be viewed directly from the Government of Chhattisgarh http://eproc.cgstate.gov.in from 01.04.2026 at 15:00 Hours. (IST) onwards. Executive Engineer Municipal Corporation, Korba (C.G.)			



OFFICE OF THE COMMISSIONER MUNICIPAL CORPORATION RAIPUR (C.G.)

e-Procurement Tender Notice

Main Portal: <http://eproc.cgstate.gov.in>

(First Call)

NIT NO: /38/15FC/RMC/2026

RAIPUR DATED : 08/04/2026

Online bids are invited for the following works of works up to 04/05/2026 at 17:30 hours.

System Tender No.	Name of work	Amount of the Estimate	Cost of Tender form	Earnest Money Deposit	Time allowed for Completion
188640	Selection of Agency for Public Awareness Activity and Customized IEC Activities Related to My Bharat Portal Under 15th Finance Commission (FY 2024-25)	50.00 Lakhs	5,000/-	38,000/-	12 months

The details can be viewed and downloaded online directly from the Government of chhattisgarh e-Procurement Portal <https://eproc.cgstate.gov.in> from 08/04/2026, 17:30 Hours (IST) on wards.

For more details on the tender and bidding process you may please visit the above mentioned portal.

Note:-

1. All eligible / interested contractors are mandated to get enrolled on e-Procurement portal.

2. Contractors can contact Help Desk for any clarification of their doubts regarding the process of Electronic Procurement System.*Help Desk at Toll Free No. 18004199140* or through Email ID helpdesk.eproc@cgswan.gov.in

3. For More Details please download NIT details.

4. Contact No. 7580888088

EXECUTIVE ENGINEER

MUNICIPAL CORPORATION

RAIPUR (C.G.)

घरों से निकलने वाले गीला व सूखा कचरों को सफाई मित्र (वाहन) को दें।

सूडूकु नवताल - 6200							****☆ मध्यम	
4	6		3	8	9	7		
	1		9	6	5	4		
				8				
4		5			8			
2	5		4	6	1			
3				1	7			
5	9		7	2	6			
7	6	4	3	9	2			

सूडूकु नवताल - 6199 का हल												
■ प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.												
■ प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.												
■ पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.												
■ पहले का केवल एक ही हल है.												
5	7	2	3	8	4	1	9	6				
8	6	1	9	2	5	7	3	4				
3	9	4	1	6	7	5	8	2				
2	5	7	4	1	3	8	6	9				
4	8	6	5	9	2	3	7	1				
1	3	9	6	7	8	4	2	5				
6	2	3	7	4	1	9	5	8				
9	4	5	8	3	6	2	1	7				
7	1	8	2	5	9	6	4	3				

शब्द पहेली- 6189 का हल												
स	ज	र	ज	मि	मि	स	न					
र	बु	र	द	र	ही	न						
क	क	ग	ह	ह	ग							
स	ल	की	र	क	ल	क	म	ई				
जो	ग	क	न	श	ख							
र	न	मी	ग	ल	भा	ब	ही	न	ल			
अ	क	ल	शू	ल	नी	र	ग	ल				
य	न	ग	ख	र								
ग	ल	म	ह	क	स	मी						
क	इ	क	न	इ	ल	र	त	य				

मुदित भटनागर
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

Dr. Juneja's

डा.ऑर्थो®

Ayurvedic Oil, Capsules, Spray & Ointment

8 गुणकारी आयुर्वेदिक तेलों से बना

डा. ऑर्थो तेल जोड़ों के दर्द को जड़ से कम करने में विशेष सहायता करता है।

मात्र 8-10ml तेल दिन में सिर्फ एक या दो बार हल्के हाथों से पीड़ित अंग पर मालिश करें।

ASIA'S MOST PROMISING BRAND

Dr. Ortho®

An Ayurvedic Medicine

Helpful in Painful Conditions

20% EXTRA

Helpful in Painful Conditions

20% EXTRA

Clinically Tested*

*For efficacy and safety.

घुटना दर्द

गर्दन दर्द

कलाई दर्द

कमर दर्द

Helpline : 7876977777 | www.drorthooil.com | Available at all medical & general stores

ये है भारत का लव मैरिज कैपिटल! हर हीर को मिल जाता है रांझा, परिवार भी करता है सपोर्ट

आइजोल। भारत में आज भी ज्यादातर शादियां अरेज्ड होती हैं और लव मैरिज को कई परिवार टेबू समझते हैं। अगर दो लोगों को आपस में प्यार है और उनकी कास्ट अलग है तो आज भी अधिकांश परिवार वाले शादी को राजी नहीं होते। भारत के कई राज्यों में तो लव मैरिज करने पर परिवार वाले जान के दुश्मन भी बन जाते हैं। लेकिन, देश के उत्तर-पूर्व में एक ऐसा राज्य है जहां लव मैरिज ना सिर्फ आम है, बल्कि परिवार भी इसे खुशी-खुशी सपोर्ट करता है। हम बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं मिजोरम की, जहां ज्यादातर कपल लव मैरिज ही करते हैं।

सबसे आगे मिजोरम

मिजोरम में इंटर-कास्ट और लव मैरिज की दर पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत में सिर्फ 5% शादियां इंटर-कास्ट होती हैं, जबकि मिजोरम में यह आंकड़ा 55% तक पहुंचता है। कई सर्वे और रिपोर्ट्स में मिजोरम को लव मैरिज के मामले में नंबर-1 बताया गया है। यहां लड़का-लड़की खुद अपना साथी चुनते हैं, परिवार विरोध की बजाय सलाह और आशीर्वाद देता है।

क्यों ज्यादा होती है लव मैरिज?

मिजोरम मुख्य रूप से ईसाई बहुल राज्य है। ईसाई संस्कृति में व्यक्तिगत पसंद को ज्यादा महत्व दिया जाता है। मिजो समाज में महिलाओं की स्थिति भी मजबूत है। हालांकि पूर्ण मातृसत्तात्मक नहीं, लेकिन महिलाओं को परिवार और समाज में अच्छा दर्जा मिलता है। लड़कियां पढ़ती हैं, नौकरी करती हैं और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेती हैं। यहां 'हीर-रांझा' वाली कहानी सच होती दिखती है। लड़का-लड़की स्कूल, कॉलेज या काम के दौरान एक-दूसरे से प्यार करते हैं और परिवार को बताते हैं। ज्यादातर मामलों में परिवार सहमत हो जाता है। अगर कोई छोटी-मोटी आपत्ति होती है तो चर्चा या परिवार के बुजुर्ग सलाह देकर मामला सुलझा देते हैं।

तलाक के मामले भी अधिक

हालांकि, एक फैक्ट ये है कि यहां डिवोर्स रेट भी अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा है, लेकिन इसका कारण महिलाओं की स्वतंत्रता और जागरूकता को माना जाता है। मिजोरम में महिलाएं घर की मुखिया की भूमिका निभाती हैं। वे फैसले लेने में बराबर की भागीदार होती हैं। लड़कियों की शिक्षा और स्वावलंबन पर खास ध्यान दिया जाता है। इसी वजह से लव मैरिज में लड़की की राय सबसे ज्यादा मायने रखती है। सोशल मीडिया और सर्वे रिपोर्ट्स में मिजोरम को बार-बार 'लव मैरिज कैपिटल' जैसे नामों से पुकारा जाता है।

रोचक खबरें

70 साल के शेख ने की 19 की लड़की से शादी, तोहफे में दी करोड़ों की कार

रियाद। उम्र का फर्क हो या ना हो, अमीरी और लगजरी के आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है। सऊदी अरब में हुए एक वीडिंग का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इस शादी में दूल्हा और दुल्हन के बीच उम्र के फासले ने जितना लोगों को हैरान किया है, उतना ही वीडिंग गिफ्ट्स की लिस्ट ने भी। एक 70 साल के अमीर शेख ने 19 साल की जवान लड़की से शादी कर ली है। शादी के बाद शेख ने अपनी नई बेगम को इतने भारी-भरकम तोहफे दिए हैं कि पूरी दुनिया हैरान है। लोग इस शादी को पैसे की बजाय मोहम्मल बता रहे हैं। इसकी खूब चर्चा हो रही है। शादी के तुरंत बाद शेख ने अपनी दुल्हन को एक नई रॉल्स रॉयस लगजरी कार गिफ्ट की। इसके अलावा उन्होंने करीब 5 किलो सोने की ईंटें भी तोहफे में दीं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों और वीडियो में दुल्हन बेहद खुश नजर आ रही है। शेख और उनकी जवान बेगम साथ में खड़े नजर आए। शादी का पूरा आयोजन फिल्मी स्टाइल में हुआ। मेहमानों की भारी भीड़ थी और हर तरफ लगजरी का माहौल था। शेख ने अपनी नई पत्नी को 'जिंदगी भर लगजरी में रखने' का वादा किया है।

बारात में कचरा गाड़ी लेकर पहुंचा दूल्हा, देखते ही इम्प्रेस हो गई दुल्हन

बीजिंग। चीन के अनहुई प्रांत के सुईशी काउंटी में 28 मार्च को एक अनोखी शादी हुई जिसने पूरे सोशल मीडिया को हिला दिया। दूल्हा पान हाओनान ने अपनी बारात में 9 कचरा गाड़ियां (सेंटिक टैंक ट्रक) लेकर पहुंचा। जहां आमतौर पर दूल्हे महंगी लगजरी कारों, घोड़ों या हेलीकॉप्टर से इम्प्रेशन जमाने की कोशिश करते हैं, वहां पान हाओनान ने पूरी तरह अलग और अनोखा रास्ता चुना। सबसे हैरानी की बात यह है कि दुल्हन इस अनोखे अंदाज से इतनी इम्प्रेस हुई कि उसने शादी के बाद उसी कचरा गाड़ी में दूल्हे के साथ बैठकर विदाई ली और ससुराल के लिए रवाना हो गई। ये मजेदार शादी सोशल मीडिया के साथ ही साथ लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बनी हुई है। पान हाओनान अपने माता-पिता के साथ सीवेज और कचरा हटाने का काम करते हैं। उन्होंने फैसला किया कि अपनी शादी में भी वे उसी पेशे को सम्मान देंगे। इसलिए उन्होंने अपनी बारात में 9 सेंट्रिक टैंक ट्रक शामिल किए। बारात जब दुल्हन के घर पहुंची तो पूरा इलाका देखकर हैरान रह गया। दुल्हन ने जब यह अनोखा स्टाइल देखा तो वह मुस्कुरा पड़ी और अपने पति का साथ दिया। शादी के बाद जब विदाई का समय आया तो दुल्हन ने खुद उसी कचरा गाड़ी में बैठकर ससुराल जाने का फैसला किया।

सर्वप्रथम अत्याधुनिक

(अल्ट्रामॉडर्न) बर्न यूनिट

10 इंटेसिव आइसोलेशन केयर ग्लास केबिन,

हेपा फिल्टर/लेमिनर फ्लो 100% जीवाणु रहित ग्लास केबिन.

छ.ग. शासन से मान्यता प्राप्त

कालिडा बर्न एवं प्लास्टिक कांस्ट्रक्टिव सर्जरी सेंटर

आर.के.जी.के.सामने, चौबे कालोनी एवं पंचपेठी नाका, धर्मपुरी रोड, कलसई मौल के पास, रायपुर नाका : 9827143060/8871003060

Alay Advt.

कुदरत ने इस जीव को अनोखे तरीके से किया है तैयार

नई दिल्ली। दुनिया तरह-तरह के अनोखे जीवों से भरी हुई है, जिनकी बनावट और जीवन जीने के तरीके हमें हैरान कर देते हैं। इन्हीं में से एक दिलचस्प जीव है टिट्टू, जिसे हम अक्सर बरसात के मौसम में इधर-उधर कूदते हुए देख लेते हैं। देखने में साधारण सा लगने वाला यह हरे रंग का कीट अपनी शारीरिक रचना के कारण काफी खास होता है। इसकी

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसके कान सिर पर नहीं, बल्कि पेट के हिस्से में होते हैं। टिट्टू की यह अनोखी बनावट केवल दिखने भर की खासियत नहीं है, बल्कि इसके जीवन

और सुरक्षा से गहराई से जुड़ी हुई है। प्रकृति ने इसे इस तरह विकसित किया है कि यह अपने आसपास के वातावरण के अनुसार खुद को बेहतर ढंग से ढाल सके और खतरों से समय रहते बच सके। नहें दिखाई देने कान : लूचक्य बात यह है कि टिट्टू के ये कान सीधे दिखाई नहीं देते। ये उसके पंखों के नीचे सुरक्षित रूप से छिपे रहते हैं।

अपनी पुरानी पाबंदियों पर फिर से विचार करने की जरूरत है? क्या हार्म रिडक्शन का यह फॉर्मूला भारत में लाखों लोगों की जान बचा सकता है?

सिगरेट और स्मोकलेस में बड़ा अंतर: नई रिसर्च का सबसे बड़ा आधार यह है कि सिगरेट और स्मोकलेस तंबाकू एक जैसे नहीं हैं। सिगरेट में तंबाकू जलता है और उसी जलने से धुआं बनता है। यही धुआं शरीर के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक माना जाता है।

दुनिया के बाकी देशों का क्या अनुभव है?

सिर्फ फ्रांस ही नहीं, कई और देश भी अब 'हार्म रिडक्शन' (नुकसान कम करने) की राह पर चल पड़े हैं। जहां ब्रिटेन अपने यहां 'स्वैप टू स्टॉप' प्रोग्राम चला रहा है। जिसमें सरकार खुद स्मोकलेस किट बांट रही है, जिससे लोग सिगरेट छोड़ सकें। अब तक 1.25 लाख लोग इसकी मदद ले चुके हैं। वहीं, जापान में भी सिगरेट छोड़कर इन प्रोडक्ट्स को अपनाने वाले लोगों में से सिर्फ 1% से भी कम लोग वापस सिगरेट की तरफ लौटें हैं। साथ ही कोरिया की एक स्टडी कहती है कि इन पर स्विच करना 'सिगरेट छोड़ने' जितना ही फायदेमंद साबित हुआ।

क्या है फ्रांस की इस रिपोर्ट में?

फ्रांस की सरकारी एजेंसी एक्सेस ने करीब 2,500 साइंटिफिक रिसर्च की गहराई से जांच की। उसके बाद उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले, वे सभी के लिए चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट का मानना है कि स्मोकलेस टोबैको प्रोडक्ट्स पूरी तरह सुरक्षित तो नहीं हैं, लेकिन सिगरेट के मुकाबले इनका खतरा बहुत कम है। जहां सिगरेट जलाने पर जो धुआं निकलता है, उसमें 7,000 से ज्यादा जहरीले केमिकल होते हैं। वहीं, स्मोकलेस प्रोडक्ट्स में तंबाकू जलता नहीं है, इसलिए वे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले जहर से बच जाते हैं।

क्यों खास है ये अंग?

दरअसल, टिट्टू के पेट के पहले खंड के दोनों ओर एक बेहद पतली झिल्ली होती है, जिसे टिम्पेनल अंग कहा जाता है। यही झिल्ली उसके सुनने का मुख्य माध्यम होती है। जब आसपास से ध्वनि तरंगें आती हैं और इन झिल्लियों से टकराती हैं, तो उनमें हल्का कंपन पैदा होता है। यही कंपन टिट्टू के शरीर में संकेत के रूप में पहुंचता है, जिससे वह आवाज को पहचान पाता है। यह प्रक्रिया इंसानों के कानों से थोड़ी अलग जरूर है, लेकिन काम लगभग वही करती है। आवाज को पकड़ना और उसे समझना, फर्क सिर्फ इतना है कि जहां इंसानों के कान सिर पर होते हैं, वहीं टिट्टू ने अपने पेट को ही सुनने का सेंटर बना लिया है।

कलपक्कम प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बिजली पैदा करने के लिए तैयार

नई दिल्ली। भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में वह ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है, जिसका सपना देश के महान वैज्ञानिक डॉ. होमी जहांगीर भाभा ने दशकों पहले देखा था। तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने आज अपनी क्रिटिकलटी हासिल कर ली है। अगर आम भाषा में कहें तो इस रिएक्टर ने अब खुद से बिजली पैदा करने वाली परमाणु प्रक्रिया को नियंत्रित तरीके से शुरू कर दिया है। यह केवल एक मशीन की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारत के ग्री-स्टेज वाले परमाणु कार्यक्रम के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण स्टेज की बड़ी जीत है।

क्यों खास है यह फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी?

दुनिया के ज्यादातर परमाणु रिएक्टर 'थर्मल रिएक्टर' होते हैं, लेकिन भारत का यह पोएफबीआर एक 'फास्ट ब्रीडर' रिएक्टर है। यह रिएक्टर यूरेनियम-प्लूटोनियम मिश्रित ऑक्साइड ईंधन का उपयोग करता है। इसके चारों तरफ 'यूरेनियम-238' की एक परत होती है। इससे जब रिएक्टर चलता है, तो इससे निकलने वाले न्यूट्रॉन इस बेकर यूरेनियम-238 को प्लूटोनियम में बदल देते हैं, जिसे दोबारा ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी से प्रदूषण और कचरे की समस्या बहुत कम हो जाती है। इसको ठंडा रखने के लिए पानी की जगह तरल सोडियम का इस्तेमाल होता है, जो इसे बहुत पड़ोस बनाता है।

भारत ऊर्जा के मामले में 400 सालों तक बन सकती है आत्मनिर्भर!

क्रिटिकलटी का क्या मतलब है?

परमाणु विज्ञान की भाषा में क्रिटिकलटी का मतलब है कि अब रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फिशन की प्रक्रिया स्थिर और नियंत्रित हो गई है। इसका मतलब अब यह रिएक्टर बिजली पैदा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह किसी भी परमाणु प्लांट के लिए सबसे अहम पड़ाव होता है।

थोरियम का खजाना और भारत का मास्टरप्लान

भारत के पास दुनिया के थोरियम भंडार का लगभग 25% हिस्सा है, लेकिन थोरियम सीधे तौर पर ईंधन नहीं बन सकता। थोरियम को ईंधन बनाने के लिए उसे 'फास्ट न्यूट्रॉन' से रिएक्शन कराना पड़ता है, जो केवल कलपक्कम जैसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ही दे सकते हैं। यह सफलता भारत को ऊर्जा के मामले में अगले 400 सालों तक आत्मनिर्भर बना सकती है। इसके बाद अब हमें किसी दूसरे देश से यूरेनियम मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

यह रिएक्टर खास क्यों है?

कलपक्कम का यह 500 मेगावाट का रिएक्टर एक 'फास्ट ब्रीडर रिएक्टर' है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह जितना ईंधन इस्तेमाल करता है, उससे कहीं ज्यादा ईंधन पैदा करता है। इसके साथ ही जहां साधारण परमाणु रिएक्टरों में गर्मी कम करने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है, तो वहीं इस ब्रीडर रिएक्टर में लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम पानी की तुलना में गर्मी को बहुत तेजी से सोखता है।

दुनिया रह गई दंग भारत बना दूसरा देश!

यह रिएक्टर पूरी तरह से 'नेड इन इंडिया' है। इसे भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने दशकों की मेहनत से तैयार किया है। इस नई उपलब्धि के बाद भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है, जिसके पास व्यावसायिक स्तर पर ऑपरेशनल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हैं। इसके पहले यह कारनामा रूस ने किया है। अमेरिका, फ्रांस और जापान जैसे विकसित देश भी अभी तक इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे, लेकिन भारत ने उनसे पहले बाजी मार ली है।

होमी जहांगीर भाभा का सपना हुआ पूरा

आपको बता दें कि भारत के परमाणु कार्यक्रम को डॉ. होमी जहांगीर भाभा ने दशकों पहले तीन स्टेज में डिवाइड किया था। इसका पहला स्टेज भारी पानी रिएक्टर बनाना था, जो अभी चल रहे हैं। इसके बाद फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाना था, जिसकी शुरुआत कलपक्कम से हो गई है। अब भारत के इस प्रोग्राम का तीसरा स्टेज थोरियम आधारित रिएक्टर बनाना है, जो आने वाले समय में पूरा होगा। भारत के वैज्ञानिक इस स्टेज के लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं।

गजब का फायदा

कब्ज से राहत

गैस से छुटकारा

एसिडिटी से आराम

20% EXTRA

पेट सफा

Natural Laxative Granules & Tablets

पेट सफा

Natural Laxative Granules & Tablets

हरिभूमि कम्यूनिक्शन प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकट इवेंट प्रकाशन विवेक सिंह भारद्वाज द्वारा हरिभूमि पब्लिकेशन, रिंग रोड नं. 2, गौरवपुर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) - 495001 से प्रकाशित। प्रधान संपादक : डॉ. हिमंशु द्विवेदी, स्थानीय संपादक: स्वर्णिम शुक्ला। RNI No. CHHIN/2001/03764, फोन : 07752-401050, फैक्स : 07752-401052. e-mail : bilaspur@haribhoomi.com